घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 197- मंगलवार 19 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

वीडी सतीशन केरलम के सीएम बने

मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली,राहुल-प्रियंका मौजूद रहे...

तिरुवनंतपुरम,18 मई 2026। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट (20 मंत्रियों) को शपथ दिलाई। ऐसा 64 साल के बाद हुआ। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी, लेकिन 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

कैबिनेट में 14 नए चेहरे...

केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। इसमें सीपी जॉन और एन शमसुद्दीन,केएम शाजी,पीके बशीर और वीई अब्दुल गफूर,पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन,बिंदु कृष्णा,टी सिद्दीकी,केए थुलसी और ओजे जनीश शामिल हैं। कांग्रेस ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद भी अपने पास रखे हैं। तिरुवनचूर राधाकृष्णन को विधानसभा स्पीकर और शनिमोल उस्मान को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। केरलम विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण के बाद 22 मई को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राज्यपाल का नीतिगत संबोधन 29 मई को निर्धारित है और राज्य का बजट 5 जून तक पेश किए जाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी, खरगे,राहुल समेत तमाम नेताओं ने सतीशन को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के शपथ लेने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि वह वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई देते हैं। केंद्र सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरल की नवगठित सरकार को हरसंभव सहयोग देगी। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने एक्स पर लिखा कि वह वीडी सतीशन और पूरी मंत्रिपरिषद को हार्दिक बधाई देते हैं। कांग्रेस-यूडीएफ के सामूहिक नेतृत्व में केरल वास्तविक प्रगति और भविष्य आधारित विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। गरिमा, न्याय, स्वतंत्रता, समावेशन और सौहार्द उनकी प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केरल की जनता ने इस सरकार के लिए संघर्ष किया है और जनता की आवाज ही सरकार का मार्गदर्शन करेगी।

सीएम सतीशन ने कैबिनेट की पहली बैठक की,5 बड़े फैसले

- शपथ ग्रहण के बाद सीएम सतीशन ने कैबिनेट की पहली बैठक की। इस दौरान कई बड़े फैसले किए गए।
- 15 जून से महिलाएं केएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
- राज्य के बुजुर्गों के लिए एक विशेष विभाग बनाने की घोषणा की गई।
- आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपए बढ़ाया गया है।
- 2023 में 'नव केरल यात्रा' के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। राज्य की वित्तीय स्थिति और राजकोष पर एक 'श्वेत पत्र' जारी किया जाएगा।

ट्रक ने मैजिक को टक्कर मारी, यूपी में टीचर-इंजीनियर समेत 10 की मौत

लखीमपुर-खीरी,18 मई 2026। लखीमपुर खीरी में सोमवार सुबह 7.30 बजे मैजिक वाहन और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मैजिक वाहन में सवार थे। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हुई,जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में सरकारी टीचर और इंजीनियर भी शामिल हैं। हादसा जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर पीलीभीत-बस्ती हाईवे पर अदलीसपुर गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मैजिक वाहन लखीमपुर से सिसैया की तरफ से जा रहा था। इसे बहराइच से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक में बैठे लोगों के सिर फट गए। लोग सीट के बीच में ही फंस गए। दो लोग उछलकर बाहर रोड पर गिरे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों का 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है।

पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया,घायल जिला अस्पताल रेफर

खमरिया के सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया- ट्रक (यूपी14 एचटी5176) बरेली के नगला फरीदपुर निवासी शेर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। शेर सिंह ट्रक के दूसरे ओनर हैं। ट्रक पर गाजियाबाद की नंबर प्लेट है। ट्रक में धान की पॉलिश की बोरियां लदी हुई हैं। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। वहीं, सीएचसी खमरिया के अधीक्षक डॉ. अमित कुमार सिंह ने बताया- हादसे के बाद 2 महिलाओं और 7 पुरुषों के शव यहां लाए गए थे। कई बॉडी बुरी तरह कुचल गई थी। एक

गंभीर घायल पुरुष को जिला अस्पताल रेफर किया गया,लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।

गांव के प्रधान बोले... ओवरटेक के चक्कर में हादसा

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी नया गांव के प्रधान प्रदीप वर्मा ने बताया- मैजिक की हालत देखकर लग रहा है कि चालक ने ओवरटेक किया होगा। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराया। हादसे के बाद मैजिक में सवार 9 लोगों की अंदर ही जान चली गई। जबकि एक युवक तड़प रहा था। किसी तरह गेट तोड़कर लोगों ने उसे बाहर निकाला। उसे एंबुलेंस से भेजा गया। हादसे में जान गंवाने वाले 10 लोगों में 9 की पहचान हो गई है। इनमें दो सगे भाई पवन (23) और सोहन (21) शामिल हैं। बहराइच के मूर्तिहा गांव के रहने वाले थे। इसके अलावा अदनान (15) निवासी सिसैया गांव धौरहरा-खीरी की भी जान चली गई। पप्पू (18) निवासी देवदत्तपुर थाना खैरी घाट (बहराइच), शहजाद (35) निवासी ककरहा मूर्तिहा (बहराइच) और जुलेखा (55) निवासी धौरहरा (खीरी) की भी मौत हो गई। एक मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है।

महाराष्ट्र से नीट-यूजी पेपर लीक मामले में कोचिंग क्लासेस का मालिक गिरफ्तार

मुंबई,18 मई 2026। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) की टीम ने सोमवार को नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर शहर में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी) के मालिक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले की गहन छानबीन सीबीआई की टीम कर रही है। सीबीआई सूत्रों ने आज बताया कि नीट पेपर लीक मामले में मोटेगांवकर की सहभागिता होने का इनपुट मिला था। इसी वजह रविवार को सीबीआई ने आरसीसी के कार्यालय और मोटेगांवकर के

घर की तलाशी ली थी। इसके बाद सीबीआई ने मोटेगांवकर से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सीबीआई का सवालों का जवाब मोटेगांवकर नहीं दे सके, इसी वजह से आज सीबीआई की टीम ने मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि मोटेगांवकर नीट यूजी पेपर के लीक और सर्कुलेशन में शामिल ऑर्गनाइज्ड गैंग का एक्टिव मेंबर थे। इसके साथ ही मोटेगांवकर ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल, 2026 के एग्जाम से पहले नीट यूजी एग्जाम, 2026 का क्वेश्चन पेपर और जवाब हासिल किए थे। मोटेगांवकर ने कथित तौर पर कई लोगों को पेपर सर्कुलेट किया था। उल्लेखनीय है कि नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की ओर से 3 मई को 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी सेंटर्स पर आयोजित किया गया था।

सासाराम में ट्रेन की जनरल बोगी में लगी आग

आनन-फानन में यात्रियों को बाहर निकाला गया,20 कर्मचारियों की मदद से पाया काबू

सासाराम,18 मई 2026। सासाराम में सासाराम-आरा-पटना पैसेंजर (ट्रेन नंबर 53212) में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग ट्रेन की जनरल बोगी छ3 में लगी थी। इसके बाद बोगी से धुआं और लपटें उठने लगीं। घटना के समय ट्रेन 6 नंबर

प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में ट्रेन से उतरने लगे। कई यात्री अपना सामान छोड़कर प्लेटफॉर्म की ओर भागे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,पहले कोच के अंदर से तेज जलने की गंध महसूस हुई। इसके बाद बोगी के भीतर धुआं भरने लगा और आग की लपटें दिखाई दीं। ट्रेन सुबह 6.45 से सासाराम से खुलने वाली थी। बोगी में आग ट्रेन खुलने से पहले लग गई थी। इस दौरान यात्री ट्रेन में बैठे हुए थे। घटना की जानकारी तुरंत रेलवे कर्मियों की दो गई। फौरन मौके पर आरपीएफ और दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। सभी यात्रियों को बोगी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जिस बोगी में आग लगी थी,उसे ट्रेन से अलग कर दिया गया है। इसके बाद ट्रेन ऑपरेशन को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगने के बाद ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। सासाराम स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर किसी भी यात्री को जाने नहीं दिया जा रहा है। प्लेटफॉर्म अभी खाली करवा दिया गया है।

नॉर्वे ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया....उनका ये 32 वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान

यूरोप भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करेगा : पीएम मोदी

ओस्लो,18 मई 2026। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया है। यह नॉर्वे के सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले कल स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। पीएम मोदी ने आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वे के पीएम योनास स्टोरे के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत और

यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। पीएम मोदी के मुताबिक, यह समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस समझौते के तहत अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है।

मोदी बोले- जंग का हल सिर्फ बातचीत से निकल सकता है : नॉर्वे में मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे संघर्षों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। सिर्फ सैन्य कार्रवाई से स्थायी शांति नहीं लाई जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे दोनों नियम आधारित व्यवस्था,बातचीत और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या पश्चिम एशिया का, भारत शांति और जल्द संघर्ष खत्म कराने की हर कोशिश का समर्थन करता रहेगा। मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि दुनिया की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि हर तरह के आतंकवाद को जड़ से खत्म करना भारत और नॉर्वे की साझा प्रतिबद्धता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का समर्थन करने के लिए नॉर्वे का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में नॉर्वे भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा।

नॉर्वे बोला...भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ साझेदारी जरूरी

नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओस्लो दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता, तनाव और संघर्ष के दौर में उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना जरूरी है, जिनके साथ समान मूल्यों और हितों को साझा किया जाता है। स्टोरे ने कहा कि दुनिया में इस समय काफी तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे समय में उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना जरूरी है जिनकी सोच और मूल्य एक जैसे हों। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्वे जैसे लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग बहुत अहम है। प्रधानमंत्री मोदी की ओस्लो यात्रा दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को दिखाती है। स्टोरे ने कहा कि भारत और नॉर्वे कई नए समझौते करने जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों को काफी उम्मीदें हैं।

सरकारी मंदिरों के पुजारियों के वेतन का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा समिति बनाने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली,18 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के पुजारियों, सेवादारों और मंदिर कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों की समीक्षा के लिए एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार

कर दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की। पीठ ने कहा कि जो लोग इससे परेशान हैं, वे सीधे अदालत का रुख कर सकते हैं और कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की,जो लोग पीड़ित हैं,वे अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कहा था कि वक्फ की तरह ही पुजारियों और सेवादारों के लिए भी न्यूनतम सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। वकील ने इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया।

पहली कैबिनेट बैठक में सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला...

ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे,महिला उत्पीड़न मामलों की हाईकोर्ट जज की अगुआई में जांच होगी,मौलवी-पुजारियों का मानदेय बंद

कोलकाता,18 मई 2026। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों और महिला उत्पीड़न की जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 2 आयोग बनेंगे। दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। सरकार ने इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को 1 जून से बंद करने का फैसला किया है। साथ ही महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए देने, मुफ्त बस यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। सातवां वेतन आयोग गठित करने और ओबीसी सूची में बदलाव जैसे अहम निर्णय भी लिए गए।

महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना : कैबिनेट ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 'अन्नपूर्णा योजना' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 जून से महिलाओं को हर

महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि जो महिलाएं पहले से 'लक्ष्मी भंडार योजना' का लाभ ले रही हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार जल्द ही नया वेब पोर्टल भी शुरू करेगी, ताकि नई पात्र महिलाएं आवेदन कर सकें। राज्य सरकार ने 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की भी मंजूरी दी है। हालांकि फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत आवेदन करने वाली महिलाएं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल पहुंचने वाली महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस बिस्वजीत बसु की अध्यक्षता में आयोग बनाया है। इसमें एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी जयरामन सदस्य सचिव होंगे। आयोग कटमनी, रिश्वतखोरी, सरकारी धन के दुरुपयोग और आम लोगों से धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच करेगा। इसके दायरे में सरकारी अधिकारी,पंचायत प्रतिनिधि, बिचौलिए,ठेकेदार,एनजीओ और सहकारी संस्थाएं भी आएंगी। दूसरा आयोग महिलाओं और बच्चियों पर कथित अत्याचार के मामलों की जांच करेगा।

महाराष्ट्र के पालघर में ट्रक-कंटेनर की टक्कर...12 की मौत,25 घायल

पालघर,18 मई 2026। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सोमवार को ट्रक और कंटेनर की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक सवार 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डहाणू तहसील के बापूगांव से 100 से ज्यादा लोग एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रक में जा रहे थे। इसी दौरान पालघर जिले के धानीवरी गांव के पास सामने से आ रहे कंटेनर से ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक और कंटेनर दोनों सड़क पर पलट गए। हादसे में ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक में बैठे कई लोग उसके नीचे दब गए। मृतकों और घायलों

में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और हाईवे पुलिस मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से ट्रक में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और तुरंत कासा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना के कारण मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक बहाल कराया।

CMYK

19 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/18/2026 10:19 PM Page 2

संपादकीय

सत्ता के साथ साख भी गंवाई

वैसे तो हार-जीत एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं,लेकिन अगर आपके हिस्से अक्सर एक ही पहलू आए तो गंभीर आत्मविश्लेषण की जरूरत है। हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों ने इस पहलू को फिर से रेखांकित किया है। असम में भाजपा की हैटट्रिक को लेकर शायद कांग्रेस को भी संदेह नहीं रहा होगा। खासकर 2023 के परिसीमन के बाद सामाजिक समीकरणों पर भाजपा की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि वहां उसकी सत्ता को हिलाना फिलहाल तो आसान नहीं है।

अपनी आक्रामक भाषा और राजनीतिक प्रबंधन से भी अपनी उपयोगिता साबित कर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा आलाकमान के लाड़ले बन गए हैं। न सिर्फ असम,बल्कि समूचे पूर्वोत्तर में भाजपाई सत्ता विस्तार में हिमंत की अहम भूमिका रही। इसे देखते हुए क्या कांग्रेस को ऐसे उपयोगी नेता को गंवाने पर कोई अफसोस होता है या नहीं?

यह भी न भूला जाए कि कांग्रेस सरकारों में वरिष्ठ मंत्री रहे हिमंत ने राहुल गांधी के व्यवहार से खफा होकर ही कांग्रेस छोड़ी थी। राहुल गांधी की टिप्पणियों से तो नहीं लगता कि ऐसे उपयोगी और जनाधार वाले नेताओं के अलगाव पर कांग्रेस में कोई आत्मचिंतन चल रहा है। बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की सत्ता का 15 साल पुराना मजबूत किला ध्वस्त हो गया। देखा जाए तो ममता और उन्हें सत्ता से अपदस्थ करने में अहम भूमिका निभाने वाले सुवेंदु अधिकारी दोनों ही मूलतः कांग्रेसी हैं।

पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने एन. रंगासामी भी पुराने कांग्रेसी ही हैं, जिन्होंने अलग क्षेत्रीय पार्टी बना कर भाजपा से गठबंधन में दूसरी बार जनादेश हासिल किया है। यह कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक समझ और प्रबंधन के फर्क को भी रेखांकित करता है। कांग्रेस जहां ऐसे उपयोगी नेताओं को मान-सम्मान नहीं दे पाती,वहीं भाजपा उन्हें दूसरे दलों से भी लाकर अपने यहां समाहित कर लेती है। इस बार अकेले बहुमत मिलने के बावजूद भाजपा ने असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट जैसे मित्र दलों को संक्षिप्त मंत्रिमंडल गठन में भी स्थान दिया है,जबकि कांग्रेस के मित्र दलों की नाराजगी असम में भी मुखर होने लगी है।

कांग्रेस बंगाल में लगभग सभी सीटों पर जीतने के बाद दो पर जीत हासिल करने में भी सफल रही,लेकिन इससे विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए की साख और भविष्य पर भी सवाल उठने लग गए। बेशक इसके लिए ममता बनर्जी की जिद भी उतनी ही जिम्मेदार रही,जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल के विधानसभा चुनाव में भी सहयोगी दलों को कोई भाव नहीं दिया। आइएनडीआइए का यह विरोधाभास भी किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर साथ होते हुए भी केरलम में कांग्रेस और वाम मोर्चा आमने-सामने होते हैं। इस बार वहां कांग्रेसनीत यूडीएफ ने एलडीएफ यानी वाम मोर्चा से ही सत्ता छीनी है। बंगाल में तो यह विरोधाभास और भी विचित्र है। ममता ने कांग्रेस छोड़कर ही अलग तृणमूल कांग्रेस बनाई और अकेले दम पर 2011 में 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को उखाड़ फेंका।

यह विरोधाभास ऐसा राजनीतिक सच है,जिससे मुंह नहीं चुराया जा सकता। फिर भी राहुल गांधी चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध भाजपाई भाषा-शैली के उपयोग से बच सकते थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा नेता ममता शासन के लिए टीएमसी का गुंडाराज जैसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। उसी शब्दावली का उपयोग करते हुए राहुल ने अप्रत्याशित रूप से संक्षिप्त चुनाव प्रचार में आरोप लगाया कि ममता ने ठीक से सरकार नहीं चलाई, इसलिए बंगाल में भाजपा के लिए रास्ता खुल रहा है। भाजपा को 207 और तृणमूल को 80 सीटें देकर बंगाल के मतदाताओं ने अपना निर्णय सुना दिया तो राजनीतिक अवसरवाद फिर दिखाई पड़ा, जब ममता और राहुल दोनों के सुर बदल गए।

राहुल ने चिरपरिचित अंदाज में आरोप लगाया कि असम और बंगाल दोनों जगह चुनाव चोरी किया गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीचे से खिसकते ही तृणमूल सुप्रीमो की ममता भी आइएनडीआइए के लिए सहानुभूति जाग उठी। किस-किस घटक दल नेता ने फोन किया और मुलाकात की,इसका विवरण मीडिया से साझा करते हुए ममता ने आह्वान किया कि भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस और वाम दलों समेत सभी को साथ आना चाहिए। स्वाभाविक ही है कि वाम मोर्चा और कांग्रेस ने इस आह्वान पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है,लेकिन आक्रामक राजनीति से भाजपा के बढ़ते सत्ता-वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इसके बावजूद यह तय दिख रहा है कि परस्पर राजनीतिक शह-मात का खेल भी जारी रहेगा।

सिस्टम का सच : हादसे पर होश, वसूली पर जोश...फिर बेहोशी

प्रो.आर.के.जैन 'अरिजीत'
बड़वानी,मध्यप्रदेश

पिता के हाथों में जली हुई देह,और सिस्टम ने कहा...दुर्घटना
जिस लापरवाही ने बच्चे को जिंदा जलाया,वो आज भी सड़क पर है...

शाजापुर-मक्सी मार्ग पर नेशनल हाईवे-52 स्थित गोलवा के समीप होटल जैन पथ से जब इंदौर-ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस बस आगे बढ़ी,तब किसी यात्री ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले कुछ मिनट मौत की दहशत में बदल जाएंगे। कोई फोन पर अपनों से बात कर रहा था, तो कोई सफर की थकान उतार रहा सबकुछ सामान्य और शांत था। तभी बस के भीतर अचानक जलती वायरिंग की तेज बदबू फैलने लगी। यात्रियों ने घबराकर ड्राइवर और कंडक्टर को धुआं उठने व शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई,लेकिन चेतावनी अनसुनी कर दी गई।

सफर के बीच बस में आग भड़क उठी और वह कुछ ही क्षणों में लपटों में घिर गई। धुएं,चीखों और बचने की कोशिशों के बीच चार वर्षीय अनय जैन सीट के नीचे फंस गया और आग की चपेट में आ गया। बस में न तो कार्यशील अग्निशमन यंत्र था और न ही इमरजेंसी एग्जिट सही हालत में। यह सिर्फ तकनीकी खामी नहीं,बल्कि लापरवाही और बदहाल व्यवस्था की गंभीर सच्चाई थी,जिसने पिता की आंखों के सामने उनके मासूम बेटे को छीन लिया। इसे केवल दुर्घटना कहना सच को कम करके दिखाना होगा। सबसे बड़ा सवाल आग लगना नहीं, बल्कि उसका कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो जाना है। तकनीकी खराबी किसी भी वाहन में हो सकती है,पर मजबूत सुरक्षा इंतजाम उसे त्रासदी बनने से रोकते हैं। यदि बस में अग्निशमन यंत्र चालू हालत में होता,इमरजेंसी गेट समय पर खुल जाता या वायरिंग की जांच हुई होती, तो शायद यह मासूम आज जिंदा होता। मगर निजी बस संचालन में सुरक्षा को बोझ माना जाता है। ज्यादा सीटें,कम खर्च और अधिक मुनाफे की सोच ने यात्रियों की सुरक्षा को हाशिये पर धकेल दिया है। खराब वायरिंग,ज्वलनशील सामग्री और केवल कागजों पर फिटनेस अब सामान्य सच्चाई बन चुकी है।

धधकती बस की लपटों ने केवल जानें नहीं लीं,बल्कि परिवहन व्यवस्था की पोल भी खोल दी। बिना सुरक्षा उपकरणों वाली बस आखिर सड़क पर कैसे दौड़ रही थी? फिटनेस प्रमाणपत्र किस आधार पर मिला? क्या किसी ने कभी इमरजेंसी गेट की जांच की? सच यह है कि परिवहन विभाग में सुरक्षा अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है और नियमों पर समझौते भारी पड़ते हैं। हर हादसे में ड्राइवर-कंडक्टर को दोषी ठहरा दिया जाता है,जबकि असली जिम्मेदार अक्सर बच निकलते हैं।

बसों में लगने वाली आग अब चौंकाने वाली घटनाएं नहीं रहीं, बल्कि व्यवस्था की आदत बन चुकी हैं। हर कुछ महीनों में कोई न कोई बस धधकती दिखाई देती है और फिर वही घिसा-पिटा क्रम शुरू होता है–अचानक जांच अभियान,कुछ चालान, कड़े बयान और फिर सब शांत। हादसे बदलते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं। इस बार भी कुछ दिन बसों की चेकिंग होगी, अधिकारी फोटो खिंचवाएंगे,प्रेस नोट जारी होंगे और फिर पुरानी ढर्रा लौट आएगा। समस्या नियमों की नहीं,उन्हें सख्ती से लागू करने की नीयत की है।

यह सिर्फ एक बस हादसा नहीं,बल्कि जिम्मेदार तंत्र की सामूहिक विफलता है। दोष केवल ड्राइवर,कंडक्टर या मालिक का नहीं,बल्कि जिस रूट से

बस गुजरी, वहां के आरटीओ अधिकारी,परिवहन प्राधिकरण,स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागीय जिम्मेदार भी बराबर के दोषी हैं। बिना जांच फिटनेस प्रमाण-पत्र कैसे जारी हुए? इमरजेंसी एग्जिट बंद क्यों था? खराब वायरिंग और ज्वलनशील सीटों पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2023 से दिसंबर 2025 तक देश में 45 बस अग्निकांड हुए, जिनमें 64 लोगों की मौत और 145 लोग घायल हुए। राजस्थान सबसे ज्यादा मौतों वाला राज्य रहा, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कई हादसे सामने आए। इतने भयावह आंकड़ों के बाद भी व्यवस्था का सुस्त बने रहना सबसे बड़ा खतरा है।

हर बड़े बस हादसे के बाद कुछ दिनों तक सड़कों पर सख्ती नजर आती है,फिर व्यवस्था दोबारा ढर्रे पर लौट जाती है। जांच,चालान और जब्ती केवल दिखावा बनकर रह जाते हैं। बस संचालकों को मालूम है कि राजनीतिक संरक्षण और अफसरशाही की सांठगांठ अंततःउन्हें बचा लेगी। इसलिए एआईएस-052 और एआईएस-119 जैसे सुरक्षा मानक सिर्फ फाइलों में कैद हैं। फायर सिस्टम,अग्निशमन यंत्र,इमरजेंसी एग्जिट और अग्निरोधक सामग्री जैसी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं मुनाफे के लिए जानबूझकर नजरअंदाज कर दी जाती हैं ताकि ज्यादा बर्थ लगाकर अधिक कमाई की जा सके।

सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि बस सुरक्षा के नियम मौजूद हैं,लेकिन उनका पालन गायब है। फिटनेस जांच, फायर सेफ्टी सिस्टम और सुरक्षित निर्माण सामग्री अनिवार्य होने के बावजूद ज्यादातर बसों में ये केवल कागजों तक सीमित हैं। कई बसों की खिड़कियां आपात स्थिति में खुल ही नहीं पातीं। इमरजेंसी गेट सामान रखने की जगह बन जाते हैं और अग्निशमन यंत्र सिर्फ दिखावे के लिए टंगे रहते हैं। यह बस भी उसी मुनाफाखोर सोच का शिकार थी,जहां यात्रियों की जान से ज्यादा कमाई को महत्व दिया गया।

यह हादसा राजनीति और प्रशासन की संवेदनहीनता भी उजागर करता है। जिस मार्ग पर यह बस रोज चलती थी, वहां कितनी बार सख्त जांच हुई? कितनी बार किसी वरिष्ठ अधिकारी ने खुद बसों की हालत देखी? जवाब लगभग शून्य है। कारण साफ है–इन बसों में आम लोग सफर करते हैं, जिनकी मौतें व्यवस्था को झकझोरती नहीं। यदि किसी रसूखदार परिवार का सदस्य इसमें फंसा होता,तो पूरे प्रदेश में तुरंत सख्ती दिखती। मगर गरीब और मध्यमवर्गीय यात्रियों की मौतें आखिर कार सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाती हैं।

सवाल सिर्फ सरकार और प्रशासन पर नहीं,समाज पर भी उठते हैं। हम सस्ती टिकट और एसी देखकर बस चुन लेते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि इमरजेंसी गेट काम करता है या अग्निशमन यंत्र मौजूद भी है या नहीं। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा उमड़ता है, मगर अगली यात्रा में वही लापरवाही दोहराई जाती है। जब तक यात्री सुरक्षित बस,तभी सफर जैसी सोच के साथ संगठित नहीं होंगे,तब तक न बस संचालकों पर दबाव बनेगा,न विभाग जागेंगे। अनय जैसे मासूमों की मौत केवल सिस्टम नहीं,हमारी सामूहिक चुप्पी की भी कीमत है। अब समय केवल संवेदनाएं जताने का नहीं, कठोर सुधार लागू करने का है। केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत राष्ट्रीय बस सुरक्षा कोड लागू करना चाहिए। हर बस में जीपीएस, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, फायर सेफ्टी सिस्टम और तीन महीने में फिटनेस जांच अनिवार्य हो। हर बड़े हादसे की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यूरोप और अमेरिका में बस अग्निकांड इसलिए दुर्लभ हैं, क्योंकि वहां नियम सिर्फ बनाए नहीं जाते, सख्ती से लागू भी होते हैं।

धधकती बस ने फिर साबित कर दिया कि परिवहन तंत्र भीतर से कितना खोखला है। जब तक कुछ दिन सख्ती, फिर सब सामान्य वाली सोच नहीं बदलेगी, तब तक मासूम यात्री यूं ही मरते रहेंगे। जवाबदेही केवल ड्राइवर तक सीमित नहीं हो सकती; अधिकारियों से मंत्रियों तक हर जिम्मेदार व्यक्ति कटघरे में हो। सिर्फ आश्वासन नहीं, ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां किसी यात्री को जिंदा जलकर न मरना पड़े। वरना अगली बस फिर किसी हाईवे पर जलेगी,लोग फिर खिड़कियां तोड़ेंगे,कोई पिता फिर बच्चे की जली देह उठाएगा और देश फिर सब भूल जाएगा। तब सबसे बड़ा सवाल हादसा नहीं,उसे होने देने वाली हमारी चुप्पी होगी।

छत्तीसगढ़ भाजपा में बदलाव के मायने

दिवाकर मुक्तिबोध
रायपुर,छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के अगले चुनाव के लिए करीब ढाई वर्ष शेष है। नये चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2028 में होंगे। भाजपा की चुनाव तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश कार्य समिति व कोर कमेटी से कुछ पुराने वरिष्ठ सदस्यों को विदा कर नये व ऊर्जावान साथियों को शामिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय नेतृत्व चुनाव के पूर्व अपेक्षाकृत नयी टीम को मैदान में उतारना चाहता है। फिलहाल जो बदलाव हुए हैं,वे चुनाव में उजली संभावनाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इस प्रक्रिया में विरोध व असंतोष की लहर का उठना स्वाभाविक है,पर फिलहाल उसकी गति मंद है। कोर कमेटी से सात दिग्गज नेताओं पुन्नूलाल लाल मोहले,गौरीशंकर अग्रवाल,बृजमोहन अग्रवाल,राम विचार नेताम,विक्रम उसेंडी, रेणुका सिंह व वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर रमनसिंह को बाहर कर दिया गया है। ये सभी अलग-अलग अवधि मे सरकार व संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके है। इनके स्थान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी,पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल,लता उसेंडी व शिवरतन शर्मा को लिया गया है। प्रदेश कार्य समिति में भी बदलाव किया गया है। 23 विधायकों को सदस्य नहीं बनाया गया जबकि परंपरागत रूप से पार्टी के सभी विधायक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य समिति में रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की नयी टीम में 14 मंत्री व 17 विधायकों को जगह दी गई है। विधान सभा में भाजपा विधायकों की कुल संख्या 54 है।

केन्द्रीय नेतृत्व के मिजाज व कार्यशैली को देखते हुए यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। भाजपा प्रयोगधर्मी पार्टी है. पुराने व पके हुए नेताओं को मुख्य धारा से हटाने की प्रक्रिया पूर्व में अहिस्ता-अहिस्ता और अब कुछ तेज गति से शुरू है। पिछले दस वर्षों में चाहे संगठन के मामले हों या विधान सभा या लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन का मसला हो,पार्टी ने ऐसे-ऐसे नेताओं को टिकिट दी जिनकी राजनीतिक पहचान खास नहीं थी। नेतृत्व ने जोखिम भरे निर्णय लिए जो कभी गलत साबित नहीं हुए। यह अलग बात है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा और आरएसएस की जमीनी ताकत चुनावों में अपना असर दिखाती रही। लगभग तमाम चुनावों में प्रत्याशी नहीं पार्टी जीतती रही है। इसलिए अनेक मामूली से मामूली नेता भी सांसद व विधायक बन गए और कुछ को मंत्री बनने का भी सौभाग्य मिला। भाजपा की नीति बहुत स्पष्ट है। यहां नेता नहीं संगठन सर्वोपरि है इसलिए कोई भी जीत व्यक्ति की नहीं,पार्टी की मानी जाती है। इसलिए कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी पार्टी आगे-पीछे नहीं देखती। छत्तीसगढ़ इसका ताजा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मामले में राष्ट्रीय नेतृत्व की कथित सलाह पर प्रादेशिक नेतृत्व ने कोर कमेटी व कार्य समिति से वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी करके स्पष्ट संकेत दिया है कि उनके सक्रिय राजनीति से रिटायर होने का वक्त आ गया है।

कोर कमेटी से हटाए गए रमनसिंह पंद्रह वर्षों तक मुख्य मंत्री रहने के बाद अब विधान सभा अध्यक्ष हैं। 2023 के विधान सभा चुनाव के दौरान काफी समय तक उनकी कोई खास पूछ-परख नहीं हुई थी। एक तरह से वे हाशिए पर थे। प्रारंभ में उन्हें चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों से बाहर ही रखा गया लेकिन नेतृत्व को इस बात का अहसास होते ही कि पूर्व मुख्य मंत्री की उपेक्षा पार्टी को भारी पड़ सकती है,उन्हें पुनः मुख्य धारा में लाया गया। भाजपा ने चुनाव जीता और रमनसिंह सिंह की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें एडजस्ट किया गया। वे विधान सभा अध्यक्ष बना दिये गये। बहुत संभव है कि यह उनका आखिरी राजनीतिक सफर हो। उनकी उम्र तथा स्वास्थगत समस्याओं को देखते हुए नहीं लगता कि उन्हें अगले चुनाव की टिकिट दी जाएगी। अलबता यदि वे दिलचस्पी दिखाएं तो उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। चर्चा रही है कि 2018 के चुनाव में पार्टी की बुरी हार के बाद उन्हें इस आशय का प्रस्ताव दिया गया था जिसे उन्होंने मंजूर नहीं किया।

कोर कमेटी से जो अन्य नेता बाहर किये गए हैं,उनमें से बृजमोहन अग्रवाल को छोड़कर शेष की सक्रियता पर सवाल उठते रहे हैं। जिन विधायकों को कार्य समिति में स्थान नहीं मिला,वे भी हैरान परेशान हैं. उनके असंतोष की जो धीमी लहरें उठ रही हैं उसके विशेष मायने नहीं हैं लेकिन असंतुष्ट बृजमोहन अग्रवाल का मामला सबसे अलग माना जा रहा है। यह बहुत स्पष्टतः नज़र आता रहा है कि रायपुर के सांसद पर केन्द्र विशेषकर मोदी मेहरबान नहीं है जबकि वे प्रदेश भाजपा के ताकतवर व खूब लोकप्रिय

नेता हैं। चुनाव संचालन में बेजोड़ माना जाने वाले इस नेता को पार्टी का ट्रबल शूटर भी कहा जाता रहा है। यही नहीं हर कठिन परिस्थितियों में उन्होंने स्वयं को साबित भी किया। राज्य के अनेक उपचुनाव में पार्टी की जीत के पीछे बृजमोहन की रणनीति कारगर रही है। उन्हें संसदीय कार्यों का भी लंबा अनुभव है। वे मध्यप्रदेश के जमाने में और बाद में अलग बने छत्तीसगढ में लगातार विधान सभा सदस्य और महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। बृजमोहन अग्रवाल के बढ़ते कद से जो विरोधी आतंकित रहे हैं उनमें डॉक्टर रमनसिंह का भी नाम लिया जाता है. उन्होंने अपने पन्द्रह वर्षों के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में बृजमोहन के पर कतरने शुरू किए। उनके मुकाबले में तब के अनुभवहीन मंत्री राजेश मूणत को खड़ा किया गया। उनकी पीठ खूब थपथपाई गई। मूणत ताकतवर मंत्री कहे जाने लगे किंतु तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद बृजमोहन की राजनीतिक सेहत पर फर्क नहीं पड़ा। न तो उनकी राजनीतिक सक्रियता घटी और न ही लोकप्रियता कम हुई।

फिर भी उनके खिलाफ प्रयास जारी रहे. 2023 के विधान सभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद यद्यपि वे विष्णुदेव साय सरकार में शामिल कर लिए गए लेकिन पार्टी के केन्द्रीय प्रमुखों ने उन्हें प्रदेश की राजनीति से दूर रखने का मन पक्का कर लिया था। मौका मिला छह माह बाद ही हुए 2024 के लोकसभा चुनाव का। उनकी अनिच्छा के बावजूद उन्हें रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से टिकिट दे दी गई। वे राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ चुनाव जीत गए। बृजमोहन सांसद जरूर बन गए हैं किन्तु प्रदेश की राजनीति में वैसे ही सक्रिय है जैसे विधायक व मंत्री रहते हुए थे। उनका मानना है कि विरोधी कितनी भी कोशिश कर लें,उनका कुछ नहीं बिगाड पाएंगे क्योंकि उनके पीछे जनता की ताकत है. कोर कमेटी में अब वे नहीं हैं किंतु प्रदेश की जनपक्षधरीय राजनीति में उनका दखल कायम है।

किंतु यह मान लेना चाहिए कि अब भाजपा में बृजमोहन की राजनीति ढलान पर है। यदि कोई चमत्कार हो जाए और देर-सबेर उन्हे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया जाए या कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाए तो बात अलग है लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद कम ही नज़र आती है. लेकिन पार्टी को इस तथ्य पर भी विचार करना होगा कि बृजमोहन जैसे वरिष्ठ व अनुभवी नेता को किनारे करने से चुनाव में पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है।

बहरहाल कोर कमेटी व कार्य समिति से दिग्गज नेताओं को बाहर किए जाने के बाद सरकार व संगठन से नाराज असंतुष्टों की लंबी कतार बनती जा रही है। राज्य विधान सभा के अब तक के सत्रों में विष्णुदेव साय सरकार को दोहरे मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। मुख्य विपक्ष कांग्रेस तो है ही,दूसरा उसका अपना प्रतिपक्ष है अर्थात अपनी ही सरकार से तल्ख सवाल करने वाले वे विधायक हैं जो असंतुष्ट खेमे का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सवाल है कि क्या केन्द्रीय नेतृत्व तथा प्रदेश संगठन कथित असंतुष्टों की मिजाज पुर्सी करेगा? उन्हें शांत करने के लिए कोई मीठी या बहुत कडवी दवाई दी जाएगी ? भाजपा की राजनीति को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी पार्टी से विद्रोह करने की स्थिति में नहीं है। लिहाज़ा चाय की प्याली में असंतोष का जो थोडा बहुत उबाल दिखाई पड़ रहा है वह कुछ समय में ही झाग की तरह अपने आप नीचे बैठ जाएगा। लेकिन यदि कार्यकताओं की पूछ-परख नहीं होगी,सत्ता व संगठन में उन्हें सम्मान नहीं मिला,सरकार से संबंधित छोटे-मोटे कार्यों के लिए भी उन्हें तरसाया गया तो जाहिर है असंतोष का लावा अंदर ही अंदर खदबदाता रहेगा और अवसर मिलते ही बाहर आ जाएगा। बीते ढाई वर्ष में साय सरकार व संगठन के कामकाज से ऐसी स्थिति धीरे-धीरे बनती जा रही है।

फिलहाल राज्य संगठन के संदर्भ में किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की प्रतीक्षा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन की कार्यकारिणी के शीघ्र गठन की उम्मीद की जा रही है। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि संगठन प्रभारी महामंत्री पवन साय के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जमकर कार्य करने वालों में से किसे राष्ट्रीय संगठन में काम करने का अवसर मिलेगा या केवल जबानी तारीफ ही चलती रहेगी ? जो भी हो पर यह स्पष्ट है कि साय सरकार स्वतंत्र नहीं है। सत्ता के वास्तविक सूत्र संगठन के चंद नेताओं के हाथ में है जिनमें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पवन साय का नाम विशेष रूप से चर्चा में रहता है। बहरहाल 2028 का चुनाव भाजपा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि सरकार की कमजोरियां संगठन पर बोझ की तरह सवार रहेंगी।

फंगल संक्रमण : भारत के सामने उभरता नया स्वास्थ्य संकट?

सुभाष बुड़ावनवाला
रतलाम.मध्यप्रदेश.

महोदय,भारत में फंगल संक्रमण अब केवल सामान्य त्वचा रोग या मौसमी बीमारी नहीं रह गया है,बल्कि यह तेजी से गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले रहा है। हाल ही में देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों और विशेषज्ञ माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा जारी इंडियन फंगल इन्फेक्शन नेशनल डिक्लेरेशन ने इस खतरे को लेकर सरकार और समाज दोनों को चेताया है। विशेषज्ञों के अनुसार कई गंभीर फंगल संक्रमणों में मृत्यु दर 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो स्थिति की भयावहता को दर्शाती है।

कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का खौफ देखा था। हजारों मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोगों की जान भी गई। लेकिन यह समस्या कोविड तक सीमित नहीं रही। अब कैंडिडा ऑरिस, एस्परजिलोसिस और क्रिप्टोकोकल संक्रमण जैसे खतरनाक फंगस तेजी से फैल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कुछ फंगल प्रजातियों को क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची में शामिल किया है। भारत में मधुमेह के मरीजों की बढ़ती संख्या,अनियंत्रित एंटीबायोटिक उपयोग,प्रदूषण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और जलवायु परिवर्तन इस संकट को और गंभीर बना रहे हैं। गर्म और आर्द्र मौसम फंगस के बढ़ने के लिए अनुकूल माना जाता है। अस्पतालों में लंबे समय तक भर्ती रहने वाले मरीज, कैंसर रोगी, अंग प्रत्यारोपण कराने वाले लोग और स्टेरॉयड लेने वाले मरीज सबसे अधिक जोखिम में हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में फंगल संक्रमण की सही पहचान और निगरानी की व्यवस्था अभी भी कमजोर है। अधिकांश जिला अस्पतालों में उन्नत जांच सुविधाएं नहीं हैं। कई बार संक्रमण का पता देर से चलता है, जिससे इलाज कठिन हो जाता है। एंटीफंगल दवाएं भी महंगी हैं और कई मामलों में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। यह स्थिति भविष्य में सुपर फंगस जैसी चुनौती पैदा कर सकती है। आई-फंड घोषणा में केंद्र सरकार से राष्ट्रीय फंगल रोग नीति बनाने, विशेष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने,अस्पतालों में संक्रमण निगरानी बढ़ाने और सस्ती एंटीफंगल दवाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया है। फंगल संक्रमण को अब सामान्य बीमारी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह भारत ने टीबी और कोविड के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चलाए,उसी तरह फंगल संक्रमण के खिलाफ भी व्यापक रणनीति बनानी होगी। समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यह संकट और भयावह रूप ले सकता है।

संवेदना

प्रिया देवांगन प्रियू
गरियाबंद,छत्तीसगढ़

पुराना मैला कंबल ओढ़े बस की एक खाली सीट पर बैठी बूढ़ी भिखारन को देख, बस कन्डक्टर का पारा सातवें आसमान पर चढ़ने लगा। तू फिर आ गई!? अभी बोहनी भी नहीं हुई है और सीट जमा कर बैठ गई। किराया कौन तेरा बाप देगा? भिखारन कहीं की! सबेरे-सबेरे तेरा मुँह देखना पड़ता है। कंडक्टर गाली देते हुए तिरछी नज़र से देखने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ महिलाएं बस में चढ़ने लगीं। सीट खाली न होने के कारण खड़ा रहना पड़ा। कंडक्टर ने बूढ़ी भिखारन के दोनों हाथ पकड़ सीट से उतारना चाहा लेकिन भिखारन जम कर बैठ गई और बोलने लगी- ए मोर बस है। चुप कर पगली! मुँह बंद कर देख तेरी वजह से महिलाएं खड़ी हैं; शर्म नहीं आती तुझे, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ड्राइवर के साथ-साथ सारे यात्री उसके बारे में अनर्गल बातें करने लगे। बिचारी बूढ़ी औरत चुपचाप आँखें बंद कर बैठ गई। बस की सारी सीटें भर चुकी थी। कहीं दूर.....बस, एक गर्भवती महिला के पास जा कर रुकी। महिला अंदर आई। चेहरे से थोड़ी बीमार लग रही थी। उसने अपनी नज़र बस के हर एक कोने में घुमाई और मायूस हो कर पीछे खड़ी हो गई। भीड़ बहुत थी लेकिन उस गर्भवती महिला को सीट देने के लिए कोई तैयार नहीं था। बिचारी बोलने लगी थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हर एक की जुबान एक ही बात कह रही थी, हम भी पैसा दिए हैं; मुफ्त में थोड़ी न चढ़े हैं बस में, हम क्यों अपनी सीट दें। तभी उस बूढ़ी भिखारन की नज़र गर्भवती महिला पर पड़ी, कुछ बड़बड़ाती हुई उस महिला का हाथ पकड़ कर अपनी सीट पर बिठाई और अनजान स्टेशन में उतर गई। लोग आश्चर्य से बूढ़ी भिखारन को देखने लगे; वहीं बाकी लोगों की मानवता धूल-धूसरित होते हुए नजर आ रही थी।

राष्ट्रीयता

लक्ष्मीनारायण सेन
गरियाबंद,छत्तीसगढ़

राष्ट्र प्रेम की भाव जगा दीजिए
ऐसा रहस्य हमें सिखा दीजिए।।
एकता का पाठ पढ़ा कर सबको
घृणा राग द्वेष सब मिटा दीजिए।।
अनेकता में एकता है हमारी संस्कृति
यह बात सारे दुनिया को बता दीजिए।।
मां भारती आप से है एक आग्रह
चित मे समर्पण भाव जगा दीजिए।।
लक्ष्य मार्ग पर कदम ना रूके कभी
ऐसे शक्ति तन मन मे जगा दीजिए।।
भारतीयता का उपवन सजा कर
राष्ट्रीयता का सुमन खिला दीजिए।।
जात धर्म का ना हो कहीं खाई
ऐसा समरस भारत बना दीजिए।।
सनातन की सबको राग सुनाकर
समाज को एक हार बना दीजिए।।
सारे जात - धर्म को ताक में रखकर
जय हिन्द की नारा सब लगा दीजिए।।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना
CMYK

19 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/18/2026 10:19 PM Page 3

सड़क,बिजली और सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल

'ट्रिपल इंजन सरकार के तीनों इंजन फेल' : नेता प्रतिपक्ष शफ़ी अहमद

अंबिकापुर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,आंदोलन की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर शहर में सड़क, बिजली और सफाई व्यवस्था की लगातार बिगड़ती हालत को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफ़ी अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शहर की मूलभूत समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में अघोषित बिजली कटौती, जर्जर सड़कें और चरमराई सफाई व्यवस्था ने आम नागरिकों का जीवन बेहाल कर दिया है,लेकिन संबंधित विभाग और भाजपा शासित नगर निगम पूरी तरह गैरजिम्मेदार रवैया अपनाए हुए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि गर्मी की शुरुआत से ही अंबिकापुर शहर लगातार बिजली संकट से जूझ रहा है। बिजली विभाग द्वारा घंटों मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आपूर्ति व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा। वहीं स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को मनमाने और भारी-भरकम बिजली बिल दिए जा रहे हैं, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है।

मानसून से पहले नालों की सफाई नहीं, जलभराव का खतरा : कांग्रेस नेताओं ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि शहर के अधिकांश बड़े नाले और नालियां गंदगी से पटे पड़े हैं। सफाई नहीं होने के कारण कई स्थानों पर नाले जाम हो चुके हैं। मानसून आने में महज एक माह का समय बचा है और यदि समय रहते सफाई नहीं हुई तो शहरवासियों को जलभराव,गंदगी और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष शफ़ी अहमद ने कहा कि स्वच्छता के लिए देशभर में पहचान बनाने वाला अंबिकापुर आज निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगम ने कई महीनों से सफाई ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया, जिसके चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर अंदरूनी सड़कें तक बदहाल

ज्ञापन में शहर की सड़कों की दुर्दशा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर के बीच से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वर्षों से जर्जर स्थिति में है, लेकिन इसके सुधार की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। इसके अलावा शहर की अंदरूनी सड़कों के लिए टेंडर जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। कांग्रेस का आरोप है कि विकास कार्यों को लेकर सरकार और नगर निगम सिर्फ बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर हालात बदतर होते जा रहे हैं।

'ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह फेल

कलेक्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष शफ़ी अहमद ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथित 'ट्रिपल इंजन सरकार' पूरी तरह विफल साबित हुई है और अंबिकापुर इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत सुधारने में नाकाम रही है, राज्य सरकार बिजली संकट और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर पा रही, जबकि नगर निगम सफाई और सड़क व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। शफ़ी अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है और आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है।

कलेक्टर ने दिया समन्वय बैठक का आश्वासन

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद सरगुजा कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाकर समस्याओं के निराकरण की दिशा में समन्वय स्थापित करने का आश्वासन दिया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो पार्टी शहरवासियों के हित में बड़ा जनआंदोलन करेगी।

ये रहे मौजूद...

ज्ञापन सौंपने के दौरान संजय विश्वकर्मा, पापिंदर सिंह, मो. हसन, कलीम अंसारी, मेराज रंगरेज, विनोद एक्का, लुईस एक्का, शुभम जायसवाल, जेनेबिब एक्का, बालकेश्वर तिर्की, आशीष वर्मा, आलोक सिंह, जीवन यादव, सतीश बारी, अमित तिवारी राजा, अमित सिंह, शिवांशु गुप्ता, तरणराज बाबरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

क्रशर प्लांट में हादसा,कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान युवक की मौत

लोहे की जाली गिरने से दबा मजदूर,सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भेलाई स्थित क्रशर प्लांट में हुए हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा रविवार को कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान हुआ, जब युवक के ऊपर लोहे की भारी जाली गिर गई। गंभीर हालत में उसे अंबिकापुर मिशन अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम भेलाई स्थित सिंघल क्रशर प्लांट में कार्यरत अल्मोन को रविवार को कन्वेयर बेल्ट की सफाई के लिए लगाया गया था। सफाई के दौरान अचानक उसके ऊपर लोहे की भारी-भरकम जाली गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद प्लांट में काम कर रहे अन्य मजदूरों ने गैस कटर और जेसीबी की मदद से युवक को बाहर निकाला। इसके बाद उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया,जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया। मृतक युवक सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खाराकोना का रहने वाला था। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन रात में ही अंबिकापुर पहुंच गए थे। मृतक के साथ काम कर रहे मजदूर अर्पण एक्का ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे। मौके पर फर्स्ट एड किट तक नहीं थी और घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की भी व्यवस्था नहीं हो सकी। अर्पण एक्का ने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद मजदूरों से घटना को जेसीबी की बकेट से दबने का मामला बताने के लिए कहा गया।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप : क्षेत्र में संचालित कई क्रशर प्लांटों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किए जाने की बात सामने आती रही है। बताया जा रहा है कि जिस क्रशर प्लांट में हादसा हुआ, उसे पूर्व संचालक विजय सिंघल ने कुछ माह पहले क्रशर संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल सहित अन्य लोगों को बेच दिया था। मामले को लेकर अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रशर प्लांटों में आदिवासी मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और शिकायतों पर केवल औपचारिक कार्रवाई की जाती है।

महंगाई की मार पर कांग्रेस का वार : किराना और सराफा कारोबारियों से पूछा हाल,बोले...ग्राहक घटे,व्यापार ठप...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को शहर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के चार दिवसीय आंदोलन के तहत जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के कार्यकर्ता किराना और सराफा बाजार पहुंचे, जहां व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद कर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस ने किसान कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा सोनी के नेतृत्व में दो अलग-अलग टीमें बनाई। दोनों दलों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में दुकानों पर पहुंचकर व्यापारियों से कारोबार की स्थिति जानी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अस्वस्थता के चलते आंदोलन का संचालन नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के मार्गदर्शन में किया गया।

किराना कारोबारियों ने कहा...लोग जरूरत तक सीमित : दुर्गेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किराना और मिठाई दुकानों में पहुंचकर व्यापारियों से चर्चा की। व्यापारियों ने बताया कि महंगाई के कारण उपभोक्ताओं ने खरीदारी कम कर दी है। लोग अब केवल जरूरी सामान ही खरीद रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों का मुनाफा लगातार घट रहा है। दुकानदारों का कहना था कि सरकार की आर्थिक नीतियां छोटे व्यापारियों के हित में नहीं हैं। वहीं कई उपभोक्ताओं ने भी कहा कि आय कम होती जा रही है जबकि रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

सराफा बाजार में भी दिखा असर : महिला कांग्रेस की टीम ने सदर रोड स्थित सराफा दुकानों में पहुंचकर व्यापारियों से चर्चा की। सराफा कारोबारियों ने सोने पर बढ़े टैक्स और प्रधानमंत्री की अपील के बाद बाजार पर पड़े असर को लेकर नाराजगी जताई। व्यापारियों ने बताया कि ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है और कई दुकानों में कारीगरों की छंटनी की नौबत आ गई है। कुछ ग्राहकों ने कहा कि शादी-ब्याह का बजट भी बिगड़ गया है,क्योंकि सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

कांग्रेस बोली...आर्थिक नीतियों से टूटी आम आदमी की कमर : नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से व्यापारी और आम नागरिक दोनों परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर जनता से राष्ट्रहित में त्याग की बात करती है, वहीं दूसरी ओर महंगाई और टैक्स के बोझ से लोगों को राहत नहीं मिल रही।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चार दिवसीय आंदोलन के दौरान जनता से मिले सुझावों और सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी व्यापक अभियान चलाया जाएगा। आंदोलन में मो. इस्लाम, संजय विश्वकर्मा,इंद्रजीत सिंह धंजल, विनय शर्मा,सीमा सोनी,अनिमा केरकेट्टा,रामविनय सिंह,जगन्नाथ कुशवाहा,मदन जायसवाल, अतुल तिवारी,आलोक सिंह,जीवन यादव, चंद्रप्रकाश सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वाहन चेकिंग में बड़ा खुलासाः ओमनी कार से 760 मोबाइल और 95 किलो पायल बरामद,5 आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ओमनी कार से भारी मात्रा में अवैध मोबाइल और धातु की पायल बरामद की है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बरामद मोबाइलों के साइबर फ्रॉड समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में उपयोग होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्रे रंग की एक ओमनी कार में कुछ लोग हाट-बाजारों से चोरी और अवैध तरीके से मोबाइल एकत्र कर दूसरे राज्यों में बेचने का काम करते हैं। सूचना के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने बनारस रोड में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी के दौरान पुलिस को वाहन में रखी प्लास्टिक की बोरियों से 110 टच स्क्रीन स्मार्टफोन और 650 कीपैड मोबाइल मिले। इसके अलावा दूसरी बोरी से 95 किलो 500 ग्राम धातु की पायल बरामद हुई। पुलिस ने जब आरोपियों से सामान के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे तो वे कोई संतोषजनक जवाब या कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 2283/2026 के तहत धारा 317(2), 317(3) एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। गिरफ्तार आरोपियों में सेन्तु शेख (26), गफ्फार शेख (28), असिम शेख (23), इब्राहिम शेख (30) और माशदुल शेख (37) शामिल हैं। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद 760 मोबाइल, 95.500 किलो पायल और ओमनी वाहन क्रमांक WB 58 BP 8233 को जब्त कर लिया है। सभी आरोपियों को सोमवार को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद मोबाइलों के स्रोत,उनके उपयोग और संभावित साइबर अपराध कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इन मोबाइलों का उपयोग साइबर फ्रॉड और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा सकता था। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक अभिषेक दूबे,आरक्षक राहुल सिंह,रमन मंडल, घनश्याम देवांगन,सत्यम सिंह और सुल्तान अहमद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सट्टा कारोबार के छोटे खिलाड़ियों पर कार्रवाई बड़े आकाओं तक कब पहुंचेगी पुलिस?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस ऑनलाइन सट्टा और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे म्यूल अकाउंट के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है,लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि आखिर इन अवैध कारोबारों को संचालित करने वाले मुख्य आकाओं तक पुलिस कब पहुंचेगी। छोटे खाता धारकों और बैंक अकाउंट बेचने वालों की गिरफ्तारी तो हो रही है,लेकिन करोड़ों के ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क को संचालित करने वाले मास्टरमाइंड अब भी पुलिस पकड़ से दूर हैं। इसी बीच गांधीनगर पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए बैंक खातों की खरीदी-बिक्री कर ऑनलाइन फ्रॉड और सट्टा रकम के लेनदेन में इस्तेमाल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

1.80 करोड़ का ट्रांजेक्शन,बैंक ने दी सूचना : गांधीनगर थाना क्षेत्र निवासी वैभव सूर्यवंशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि नवापारा निवासी सुमित सिंह और अनुज सिंह ने घर निर्माण के लिए पैसों के लेनदेन का बहाना बनाकर उसके नाम से आईडीबीआई बैंक में दो खाते खुलवाए। बाद में एटीएम कार्ड,चेकबुक और पासबुक अपने पास रख लिए। कुछ समय बाद वैभव को जानकारी मिली कि उसके एक खाते से करीब 80 लाख और दूसरे खाते से लगभग 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। बैंक से सूचना मिलने के बाद उसने खाते बंद करवाए और थाना गांधीनगर में शिकायत दर्ज कराई।

पूछताछ में खुला सट्टा और फ्रॉड नेटवर्क का राज : पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी अनुज सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अलग-अलग लोगों से बैंक खाते लेकर उनमें ऑनलाइन फ्रॉड और सट्टा का पैसा ट्रांसफर कराता था। पुलिस ने आरोपी अनुज सिंह निवासी नवापारा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में सुमित सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

साइबर सेल की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल : लगातार सामने आ रहे करोड़ों के ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के बावजूद अब साइबर सेल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जब खातों में करोड़ों रुपए का लेनदेन हो रहा था, तब समय रहते निगरानी और कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जानकारों का मानना है कि यदि साइबर सेल और बैंकिंग मॉनिटरिंग एजेंसियां समन्वय के साथ ईमानदारी से जांच करें तो ऑनलाइन सट्टा और साइबर फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

10 दिनों में 20 आरोपी जेल भेजे गए : सरगुजा पुलिस के अनुसार पिछले 10 दिनों में म्यूल अकाउंट के 4 मामलों में कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने बैंक खाते और अवैध सिम कार्ड की खरीदी-बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान जारी रहने की बात कही है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे पैसों के लालच में अपने बैंक खाते, सिम कार्ड या दस्तावेज किसी को उपलब्ध न कराएं, क्योंकि ऐसे खाते साइबर अपराध और ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

निगरानी बदमाश गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)।

आपसी रंजिश में युवक के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पूर्व से निगरानी बदमाश है, जिसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी हर्षित चक्रवर्ती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 जनवरी 2025 को मेडिकल कॉलेज चौक बिसुनपुर के पास उसके साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। मामले में आरोपी वितीत बोस, शिवम मिश्रा उर्फ देवेंद्र, आयुष जायसवाल और आर्यन ढाली को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण का मुख्य आरोपी लल्ला यादव घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी चैपाटी के पास मौजूद है। सूचना पर थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर, अभिषेक दूबे एवं आरक्षक कुंदन पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कर्ज से परेशान किराना दुकान संचालक ने की आत्महत्या

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)।

कर्ज से परेशान किरानदा दुकान संचालक ने कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या कर ली। उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आशीष अग्रवाल पिता प्रेमचद उम्र 40 वर्ष शहर के महाया रोड जरहागढ़ का रहने वाला था। यह किराना दुकान का संचालन करता था। दुकान नहीं चल पा रहा था। व्यापार बढ़ाने के लिए काफी कर्ज लिया था। कुछ दिनों से यह डिपरेशन में चल रहा था। 17 मई की सुबह वह कीटनाशक सेवन कर लिया। परिजन उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को कुचला,मौत

एनएच पर शव रखकर चक्काजाम,टायर जलाकर किया प्रदर्शन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)।

एनएच-130 अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग स्थित सांड़बार बैरियर के पास रविवार शाम तेज रफ्तार अज्ञात कार ने दो युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। सोमवार को आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव सडक़ पर रखकर चक्काजाम कर दिया। टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। जानकारी के अनुसार मणिपुर थाना क्षेत्र के सांड़बार बैरियर के पास तस्लीव की टायर दुकान है। दुकान में उसका भतीजा मो. कमरान पिता मो. नसीम (20) काम करता था। रविवार शाम सुंदरपुर निवासी अनिल गढ़वाल पिता अमर साय (25) अपनी कार में हवा भरवाने दुकान पहुंचा था। कमरान टायर में हवा डाल रहा था और अनिल पास में खड़ा था। इसी दौरान लखनपुर की ओर से तेज रफ्तार सफेद रंग की कार आई और दोनों को अपनी चपेट में लेते हुए करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए निकल गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। दुकान संचालक तस्लीव दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग : सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने एनएच पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सडक़ पर टायर जलाकर विरोध जताया। लोगों का कहना था कि एनएच पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।

CMYK

19 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/18/2026 10:19 PM Page 4

15 लाख की इंटरलॉकिंग सड़क 'गायब '!

बैमा पंचायत में सड़क निर्माण पर ग्रामीणों का बड़ा आरोप,बोले...'सड़क चोरी हो गई क्या?'पांच महीने में उखड़ गई फेवर ईंट,घटिया निर्माण छुपाने सड़क पर डाल दी मुरुम

ग्रामीणों ने जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और तत्कालीन उपसरपंच पर लगाया सरकारी राशि में बंदरबांट का आरोप

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/पोड़ी बचरा,18 मई 2026 (घटती-घटना)। विकासखंड जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बैमा में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क अब ग्रामीणों के गुस्से और भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में आ गई है,गांव के मुख्य मार्ग शिवलाल के घर से आंगनबाड़ी बेलघुटरी पहुंच मार्ग तक बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं,ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में शुरू से ही गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी की गई,जिसका नतीजा यह हुआ कि सड़क महज पांच महीने में ही उखड़कर बिखर गई,ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन उपसरपंच बैमा एवं वर्तमान जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बैकुंठपुर द्वारा मनरेगा योजना के तहत लगभग 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति कराकर निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और बंदरबांट किया गया।

'मेरी पहुंच ऊपर तक है...' विरोध करने पर ग्रामीणों को मिली धमकी?

ग्रामीणों का आरोप है कि जब सड़क निर्माण कार्य चल रहा था,तभी गांव के कई लोगों ने निर्माण में घटिया सामग्री और मानक विहीन कार्य को लेकर आपत्ति जताई थी,लेकिन विरोध करने पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर धमकी दी गई कि 'मेरी पहुंच ऊपर तक है, मेरा कुछ नहीं होगा, जहां शिकायत करना है कर दो, ग्रामीणों का कहना है कि उस समय शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब सड़क की हालत देखकर पूरा गांव आक्रोशित है।

'इंटरलॉकिंग सड़क ढूंढने पर नहीं मिल रही' सड़क उखड़ी तो ऊपर डाल दी मुरुम!

ग्रामीणों ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि गांव में बनी इंटरलॉकिंग सड़क अब 'ढूंढने पर भी नहीं मिल रही ',ऐसा लग रहा है जैसे सड़क चोरी हो गई हो, आरोप है कि जब सड़क की फेवर ईंटें उखड़ने लगीं और निर्माण की पोल खुलने लगी, तब आनन-फानन में सड़क के ऊपर मुरुम डाल दिया गया ताकि घटिया निर्माण को छुपाया जा सके, लेकिन हालत यह है कि सड़क पर डाली गई मुरुम को ठीक तरीके से फैलाया तक नहीं गया, जिससे पूरा मार्ग उबड़-खाबड़ हो गया है, राहगीरों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पांच महीने भी नहीं टिक पाई सड़क,जगह-जगह से उखड़ी फेवर ईंटें-

ग्रामीणों ने बताया कि इंटरलॉकिंग सड़क बनने के कुछ ही महीनों बाद सड़क पर लगी फेवर ईंटें जगह-जगह से उखड़ने लगीं। कई ईंटें टूटकर बिखर गईं,जबकि सड़क की सतह धंसने लगी,ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया दर्जे की फेवर ईंट, गिट्टी और मसाले का इस्तेमाल किया गया,मानकों के अनुसार बेस तैयार नहीं किया गया और गुणवत्ता की पूरी तरह अनदेखी की गई,ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य सही तरीके से किया गया होता, तो सड़क कम से कम कई वर्षों तक टिकती, लेकिन यहां तो सड़क एक वर्ष भी नहीं चल पाई।

सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ, अघोषित ठेकेदारी और बंदरबांट का आरोप-गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में सरकारी धन का खुला दुरुपयोग किया गया, मनरेगा योजना के नाम पर लाखों रुपए स्वीकृत कराकर सड़क निर्माण कराया गया, लेकिन वास्तविक कार्य बेहद घटिया स्तर का किया गया,ग्रामीणों का कहना है कि पूरे निर्माण कार्य में अघोषित ठेकेदारी प्रणाली अपनाई गई और सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया,लोगों ने मांग की है कि सड़क निर्माण की तकनीकी जांच कराई जाए और जिन लोगों ने घटिया निर्माण किया है, उनसे पूरी राशि की वसूली कर शासन के खाते में जमा कराई जाए।

ग्रामीणों में भारी आक्रोश,बोले... 'गांव के विकास के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं '- ग्रामीणों ने साफ कहा है कि गांव के विकास के नाम पर सरकारी धन की लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी ने पूरे गांव को परेशान कर दिया है, ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य करने वाले जिम्मेदार लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी उठाई गई है।

बड़ा सवाल-सड़क बनी थी या सिर्फ भुगतान?

अब गांव में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर 15 लाख रुपए की लागत से बनी इंटरलॉकिंग सड़क इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? क्या निर्माण सिर्फ कागजों में मजबूत था? क्या भुगतान पहले और गुणवत्ता बाद में देखी गई? और आखिर सड़क की हालत खराब होने के बाद उसकी मरम्मत के बजाय मुरुम डालकर मामला दबाने की कोशिश क्यों की गई?

जांच हुई तो खुल सकते हैं बड़े राज

ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, सड़क निर्माण में उपयोग की गई सामग्री, भुगतान प्रक्रिया और कार्य की गुणवत्ता की जांच होने पर भ्रष्टाचार की परतें खुल सकती हैं, अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की शिकायतों को कितना गंभीरता से लेता है और क्या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

19 करोड़ की दुर्लभ 'अवलोकितेश्वर' प्रतिमा लौटेगी छत्तीसगढ़, अमेरिका से भारत लाई जा रही धरोहर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय से वर्षों पहले चोरी हुई भगवान अवलोकितेश्वर की दुर्लभ कांस्य प्रतिमा अब फिर से प्रदेश लौटने की तैयारी में है। करीब 19 करोड़ रुपए मूल्य की यह ऐतिहासिक प्रतिमा अमेरिका से भारत लाई जा रही है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर प्रतिमा को छत्तीसगढ़ वापस भेजने का आग्रह किया है। जानकारी के मुताबिक प्रतिमा फिलहाल भारत पहुंचने की प्रक्रिया में है। इसके बाद राज्य शासन उसे रायपुर लाकर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में पुनर्स्थापित करेगा। मंत्री श्री अग्रवाल प्रतिमा की रिसीविंग के लिए दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। बताया गया है कि हाल के वर्षों में अमेरिका ने भारत को लगभग 1.4 करोड़ डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन कलाकृतियां लौटाई हैं। इन्हीं में छत्तीसगढ़ की यह बहुमूल्य कांस्य प्रतिमा भी शामिल है। सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

सिरपुर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी है प्रतिमा : यह प्रतिमा वर्ष 1939 में महासमुंद जिले के विश्वविख्यात पुरातात्विक स्थल सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर परिसर के पास मिली थी। यह उस क्षेत्र में प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं के बड़े भंडार का हिस्सा थी। बाद में इसे संरक्षण के लिए रायपुर स्थित संग्रहालय में रखा गया, लेकिन चोरी के बाद यह विदेश पहुंच गई। इतिहासकारों के अनुसार प्रतिमा पर 'द्रौणग्रिदत्त' नाम अंकित है, जो प्राचीन श्रीपुर यानी वर्तमान सिरपुर का निवासी माना जाता है। इससे प्रतिमा का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। अवलोकितेश्वर की यह प्रतिमा छत्तीसगढ़ की समृद्ध बौद्ध परंपरा, प्राचीन शिल्पकला और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। सिरपुर प्राचीन काल में बौद्ध संस्कृति और कला का प्रमुख केंद्र रहा है।

सरकार ने शुरू की औपचारिक प्रक्रिया : संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह प्रतिमा केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की अमूल्य धरोहर है।

उन्होंने केंद्र सरकार से सभी औपचारिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर प्रतिमा को छत्तीसगढ़ शासन को सौंपने का आग्रह किया है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रतिमा की सुरक्षा, संरक्षण और प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि आमजन, शोधार्थी और इतिहास प्रेमी इस ऐतिहासिक धरोहर को फिर से देख सकें। अवलोकितेश्वर प्रतिमा की वापसी को छत्तीसगढ़ की खोई सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना और सिरपुर की ऐतिहासिक पहचान को नई प्रतिष्ठा दिलाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

निधन

आशा लता शर्मा

शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम कुमार शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती आशा लता शर्मा का लंबी बीमारी के बाद रायपुर में दुखद निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार,रिश्तेदारों एवं शुभचिंतकों में शोक की लहर व्याप्त है। स्वर्गीय आशा लता शर्मा का अंतिम संस्कार अंबिकापुर के शंकर घाट स्थित मुक्तिधाम में किया गया, जहां पति प्रेम कुमार शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। वे अधिवक्ता अलंकार शर्मा की माताजी एवं भाजपा नेता अभिषेक शर्मा की बड़ी माँ थीं। शहर के सामाजिक, राजनीतिक एवं विधि जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय आशा लता शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

नाम परिवर्तन सूचना

मै कुंवार सिंह .(माता/पिता/ पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री सरोता मरकाम गाँव / शहर तहसील - उदयपुर . जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य ने, अपने नाबालिग सुपुत्र/ सुपुत्री का नाम इखति (पुराना नाम) से बदल कर ईशवती (नया नाम) रख लिया है।

पालक
कुंवार सिंह
उदयपुर.जिला सरगुजा छ0ग0

नाम परिवर्तन सूचना

मै मनोज कुमार यादव (माता/पिता/ पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री स्व0 महादेव यादव गाँव/शहर आमा डुगूपारा ग्राम चकेरी पो0 परसा तहसील उदयपुर जिला -सरगुजा छ0ग0 राज्य ने, अपने नाबालिग सुपुत्र/ सुपुत्री का नाम अखिलेश यादव (पुराना नाम) से बदल कर रूपेश यादव (नया नाम) रख लिया है।

पालक
मनोज कुमार यादव
उदयपुर.जिला सरगुजा छ0ग0

न्यायालय तहसीलदार रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज दिनांक,छ0ग0

क्रमांक/884/वा0/तह0/2026
रामानुजगंज दिनांक - 18/05/2026

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम- रामानुजगंज को सूचित किया जाता है कि विषयांन्तर्गत लेख है कि आवेदक वैष्णव जायसवाल आ0 मनोज जायसवाल जाति जायसवाल वर्ग (सामान्य) निवासी रामानुजगंज थाना व तहसील रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) के द्वारा के स्वमं वैष्णव जायसवाल के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने किसी वैध प्रतिनिधि के माध्यम से पेशी दिनांक- 8/6/2026 तक इस न्यायालय में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक- 18/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(सील) तहसीलदार
रामानुजगंज
जिला-बलरामपुर-रागं0

कलेक्टर की सख्ती,वन अधिकार पत्रों का शत-प्रतिशत नामांतरण पूर्ण

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)। कलेक्टर अजीत बसंत की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में लंबित प्रकरणों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी कार्य समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जाति प्रमाण पत्र निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर मैनपाट के बीईओ और बीआरसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं सुशासन तिहार के तहत प्राप्त मांगों और शिकायतों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने अधिकारियों को कहा गया। कलेक्टर ने तहसीलदारों को फौती नामांतरण के लंबित मामलों का 15 दिनों में निराकरण करने के निर्देश देते हुए राजस्व विभाग को बुनियादी कार्यों में गंभीरता बरतने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले में वन अधिकार पत्रों का शत-प्रतिशत नामांतरण कार्य पूरा कर लिया गया है। राजस्व और वन विभाग के अंतर्गत कुल 425 वन अधिकार पत्रों का नामांतरण पूर्ण किया गया। इसके अलावा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उसी दिन पीपीओ और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आकाश चोपड़ा आ0/ पति रविन्द्र कुमार चोपड़ा जाति, निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/117, 9/120 रकबा 0.123/4, 0.04 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 22/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 07/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कनोदपाल आ0 / पति स्व0 रामप्रकाश चोपड़ा निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/42 रकबा 0.12 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 22/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक - 07/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विशाल कुमार चोपड़ा आ0/पति स्व0 अविनाश चोपड़ा जाति, निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/111 रकबा 0.041/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 22/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 07/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आकाश चोपड़ा आ0/ पति रविन्द्र कुमार चोपड़ा व अन्य 03 जाति, निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/13 रकबा 0.631/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 22/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 07/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती बरखा चोपड़ा आ0/पति कानोदपाल चोपड़ा जाति, निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9 / 100 रकबा 0.031/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 22/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 07/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोरथ कुमार आ0/पति स्व0 रामप्रकाश चोपड़ा जात निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/47, 9/61 रकबा 695, 0.011/2 वर्गफीट / एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 22/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 07/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

CMYK

कोरिया कलेक्ट्रेट का 'अमर स्टेनो' मॉडल

विभाग दूसरा,कुर्सी दूसरी...लेकिन प्रभाव ऐसा कि सिस्टम भी हुआ नतमस्तक?

- मत्स्य निगम का कर्मचारी,राजस्व विभाग की सबसे प्रभावशाली कुर्सी! दो दशक की प्रतिनियुक्ति पर उठे सवाल
- छः महीने में पदोन्नति,दो दशक की प्रतिनियुक्ति...आखिर किस संरक्षण में चलता रहा यह सिस्टम?
- कलेक्ट्रेट में स्थायी प्रतिनियुक्ति का खेल? अर्ध शासकीय कर्मचारी के हाथों में संवेदनशील फाइलों पर बहस तेज
- फाइलें,शिकायतें और प्रभाव का नेटवर्क! कोरिया कलेक्ट्रेट के चर्चित स्टेनो पर नए खुलासे
- राजस्व विभाग नहीं,फिर भी कलेक्ट्रेट की सबसे ताकतवर कुर्सी! आखिर कैसे बना यह प्रभावशाली तंत्र?
- स्टेनो की कुर्सी या समानांतर सत्ता? बदलते रहे कलेक्टर,लेकिन नहीं बदला प्रभाव
- अर्ध शासकीय कर्मचारी के हाथों में कलेक्ट्रेट की गोपनीय फाइलें! प्रशासनिक सुरक्षा पर बड़े सवाल
- प्रतिनियुक्ति या स्थायी कब्जा? दो दशक से जमे स्टेनो पर उठी जांच की मांग...

कोरिया कलेक्ट्रेट में फाइलों का खेल? शिकायतें हुईं,जांच बैठी... लेकिन कार्रवाई अब तक गायब!

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,18 मई 2026 (घटती-घटना)। सरकारी दफ्तरों में अक्सर कहा जाता है कि कर्मचारी आते-जाते रहते हैं,लेकिन व्यवस्था चलती रहती है, लेकिन कोरिया कलेक्ट्रेट में हालात कुछ अलग बताए जाते हैं, यहां वर्षों से पदस्थ एक प्रभावशाली स्टेनो को लेकर अब ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं,जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था, प्रतिनियुक्ति प्रणाली, विभागीय जवाबदेही और कार्यालयीन पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, मामला केवल एक कर्मचारी के लंबे समय तक एक कार्यालय में पदस्थ रहने का नहीं है, सवाल यह भी है कि आखिर एक अर्ध शासकीय कर्मचारी,जो मूल रूप से राजस्व विभाग का नहीं बल्कि मत्स्य निगम विभाग का बताया जा रहा है,वह दो दशक से अधिक समय तक कलेक्ट्रेट जैसे अत्यंत संवेदनशील कार्यालय में कैसे बना रहा? और उससे भी बड़ा सवाल–यदि किसी दिन कोई महत्वपूर्ण फाइल गायब हो जाए,कोई संवेदनशील दस्तावेज लापता हो जाए या कोई प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आए,तो जिम्मेदारी आखिर तय किसकी होगी? अब जब दस्तावेजों, पदोन्नति,प्रतिनियुक्ति,सर्विस बुक, शिकायतों और दबाई गई जांचों को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, तब कोरिया कलेक्ट्रेट का यह मामला केवल स्थानीय चर्चा नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर परीक्षा बनता जा रहा है।

राजस्व विभाग नहीं, मत्स्य निगम विभाग के कर्मचारी!

पूरे मामले का सबसे गंभीर पक्ष यही माना जा रहा है कि संबंधित स्टेनो मूल रूप से राजस्व विभाग के कर्मचारी ही नहीं बताए जा रहे, सूत्रों के अनुसार वे मत्स्य निगम विभाग से जुड़े अर्ध शासकीय कर्मचारी हैं,अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कलेक्ट्रेट जैसा संवेदनशील कार्यालय, जहां भूमि रिकॉर्ड,राजस्व प्रकरण, गोपनीय फाइलें,प्रशासनिक आदेश और महत्वपूर्ण दस्तावेज रहते हैं,वहां अपने विभाग के नियमित कर्मचारी के बजाय दूसरे विभाग के अर्ध शासकीय कर्मचारी को इतने वर्षों तक बनाए रखना क्या प्रशासनिक सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न नहीं है? प्रशासनिक हलकों में अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि यदि किसी दिन कोई फाइल गायब हो जाए, कोई आदेश लीक हो जाए या कोई रिकॉर्ड प्रभावित हो जाए,तो उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? क्योंकि नियमों के अनुसार यदि कर्मचारी मूल विभाग का ही नहीं है, तो कार्रवाई की प्रक्रिया भी जटिल हो जाती है, यानी जिम्मेदारी की स्थिति में मामला यह हमारा कर्मचारी नहीं और यह वहां प्रतिनियुक्ति पर था जैसे जवाबों के बीच फंस सकता है।

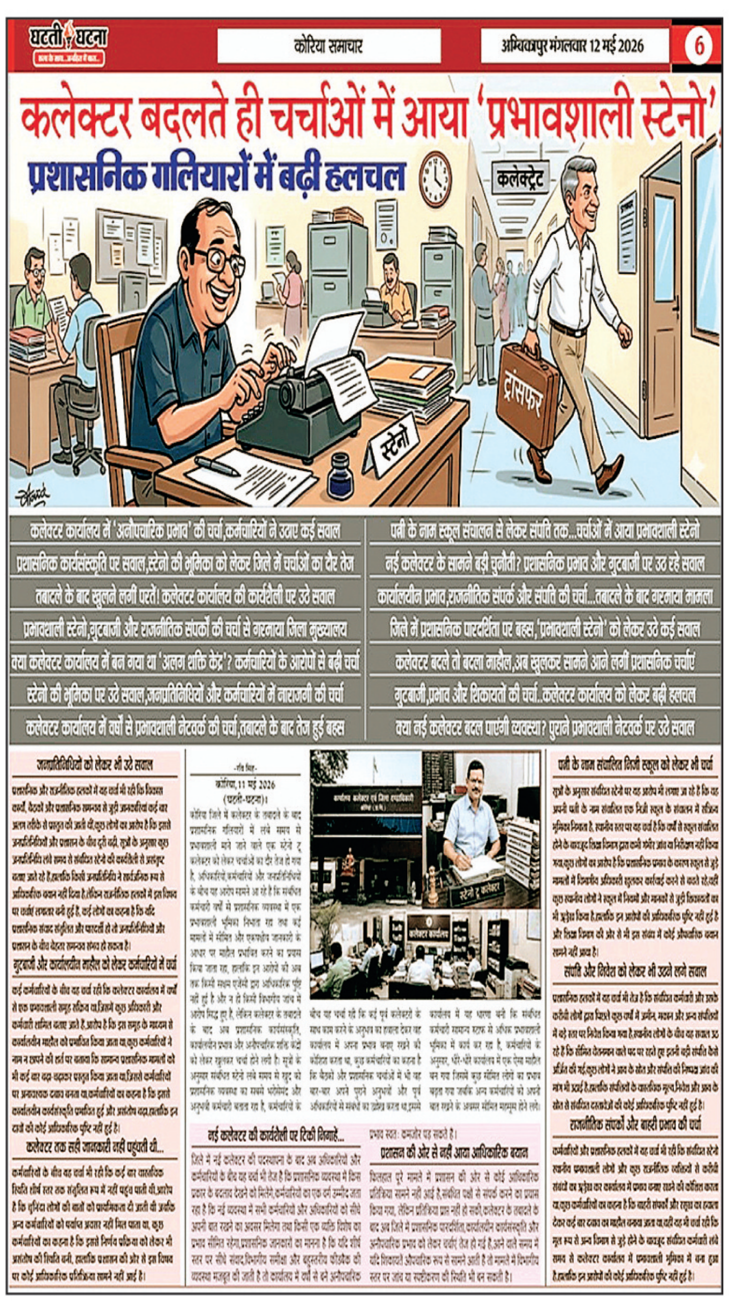

घटती घटना | कोरिया समाचार | अम्बिकापुर मंगलवार 12 मई 2026 | 6

कलेक्टर बदलते ही चर्चाओं में आया 'प्रभावशाली स्टेनो'

प्रशासनिक गलियारों में बढ़ी हलचल

कलेक्टर तक सही जानकारी नहीं पहुंचती थी...

नई कलेक्टर की कार्यशैली पर टिकी निगाहें...

प्रशासन की ओर से नहीं आया आधिकारिक बयान

राजनीतिक संपर्कों और बाहरी प्रभाव की चर्चा

घटती घटना | कोरिया समाचार | अम्बिकापुर शनिवार 16 मई 2026 | 6

कोरिया कलेक्ट्रेट का स्थायी सिस्टम या प्रशासनिक चमत्कार?

दो दशक से जमे स्टेनो कलेक्टर पर उठे सवालों की लंबी फेहरिस्त

पत्नी के नाम स्कूल और सांसद निधि का सवाल...

सबसे बड़ा सवाल–आखिर सिस्टम चला कौन रहा है?

नई कलेक्टर के सामने सबसे बड़ी परीक्षा...

छः महीने में पदोन्नति... सरकारी सिस्टम का चमत्कार या फाइलों का खेल?

प्राप्त दस्तावेजों और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित कर्मचारी घनश्याम मिश्रा की नियुक्ति 7 अप्रैल 1986 को स्टेनो टाइपिस्ट पद पर हुई थी, लेकिन सबसे अधिक हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि महज कुछ ही महीनों बाद 27 अप्रैल 1986 को उन्हें स्टेनोग्राफर बना दिया गया, अब सरकारी कर्मचारी खुद पूछ रहे हैं कि जहां सामान्य कर्मचारी वर्षों तक पदोन्नति सूची में अपना नाम ढूंढते रह जाते हैं, वहां आखिर ऐसा कौन-सा प्रशासनिक चमत्कार हुआ कि कुछ महीनों में ही पद बदल गया? व्यंग्य में कर्मचारी कहते सुने जा रहे हैं कि यदि सरकारी सेवा में इतनी तेज पदोन्नति संभव है,तो प्रतियोगी परीक्षाओं और वरिष्ठता सूची की जरूरत ही क्या है? यही नहीं,दस्तावेजों में नाम को लेकर भी चर्चा है,नियुक्ति रिकॉर्ड में घनश्याम मिश्रा नाम बताया जा रहा है, जबकि कुछ पदोन्नति संबंधी दस्तावेजों में जेपी मिश्रा नाम सामने आने की बात कही जा रही है,अब सवाल यह है कि यह केवल रिकॉर्ड की तकनीकी शैली है या फिर सरकारी दस्तावेजों का वही पुराना खेल, जहां नाम, पद और नियम परिस्थितियों के अनुसार आकार बदल लेते हैं।

प्रतिनियुक्ति या स्थायी सरकारी पट्टा?

सरकारी सेवा नियमों में प्रतिनियुक्ति सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, एक विभाग का कर्मचारी कुछ समय के लिए दूसरे विभाग में भेजा जाता है और कार्य पूरा होने पर वापस लौट आता है,लेकिन कोरिया जिले में यह प्रतिनियुक्ति अब स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था बन चुकी है,बताया जाता है कि संबंधित कर्मचारी पिछले दो दशक से अधिक समय से लगातार कलेक्ट्रेट और राजस्व विभाग में पदस्थ हैं,यानी सरकारें बदलीं...अधिकारी बदले...जिले का विभाजन हुआ...नए कलेक्टर आए...लेकिन यदि कुछ स्थायी रहा तो वह यही प्रतिनियुक्ति,कर्मचारी अब मजाक में कहते हैं सरकारी योजनाएं अस्थायी हो सकती हैं,लेकिन कुछ कुर्सियां सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि निजी विरासत जैसी लगने लगती हैं।

क्या अर्ध शासकीय कर्मचारियों के हाथों में महत्वपूर्ण फाइलों का ट्रांजैक्शन सुरक्षित है?

कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील कार्यालय में हर दिन सैकड़ों महत्वपूर्ण फाइलों का आवागमन होता है,इनमें राजस्व प्रकरण,भूमि विवाद, प्रशासनिक आदेश,गोपनीय पत्राचार, नियुक्तियां,विभागीय जांच, शिकायतें और शासन स्तर से आने वाले संवेदनशील दस्तावेज शामिल रहते हैं,ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस प्रकार की महत्वपूर्ण फाइलों और गोपनीय दस्तावेजों का संचालन किसी अर्ध शासकीय कर्मचारी के हाथों में होना प्रशासनिक दृष्टि से सुरक्षित और उचित माना जा सकता है? प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालयों में संवेदनशील शाखाओं में उन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जिनकी जवाबदेही सीधे संबंधित विभाग और शासन के अधीन स्पष्ट रूप से तय हो,क्योंकि यदि किसी दस्तावेज में गड़बड़ी हो,फाइल गायब हो जाए,आदेश लीक हो जाए या रिकॉर्ड प्रभावित हो जाए, तो जिम्मेदारी तय करना आसान होता है,लेकिन जब मामला किसी दूसरे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए अर्ध शासकीय कर्मचारी का हो,तब जवाबदेही का प्रश्न और जटिल हो जाता है, यदि भविष्य में कोई गंभीर प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आती है तो कार्रवाई कौन करेगा? राजस्व विभाग या मूल विभाग? और क्या विभागीय नियमों के तहत उतनी ही सख्ती से जवाबदेही तय हो पाएगी जितनी एक नियमित शासकीय कर्मचारी की स्थिति में संभव होती है? सूत्रों के अनुसार यही कारण है कि अब कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली को लेकर कई कर्मचारी और प्रशासनिक जानकार सवाल उठा रहे हैं,उनका कहना है कि महत्वपूर्ण कार्यालयों में फाइलों का ट्रांजैक्शन केवल अनुभव का नहीं बल्कि सुरक्षा,गोपनीयता और प्रशासनिक विश्वसनीयता का विषय भी होता है,कर्मचारियों के बीच यह चर्चा भी है कि यदि वर्षों तक एक ही व्यक्ति के हाथों से अधिकांश महत्वपूर्ण फाइलें गुजरती रहें,तो स्वाभाविक रूप से एक अनौपचारिक नियंत्रण की स्थिति बन जाती है,ऐसे में यह आशंका भी बढ़ जाती है कि कौन-सी फाइल कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी,कौन-सी शिकायत लंबित रहेगी और कौन-सा मामला दब जाएगा,यह सब प्रभावित हो सकता है, यही वजह है कि अब यह बहस केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रह गई है,बल्कि प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था और कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बन चुकी है।

कमिश्नर स्तर की जांच भी गायब?

सूत्रों के अनुसार सरगुजा कमिश्नर शिखा राजपूत द्वारा एक जांच टीम गठित की गई थी, बताया जाता है कि एक प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर को इस जांच का दायित्व भी सौंपा गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह जांच आखिर कहां पहुंची? क्या रिपोर्ट तैयार हुई? क्या किसी अधिकारी को सौंपी गई? क्या कार्रवाई प्रस्तावित हुई? या फिर वह जांच भी सरकारी फाइलों की भीड़ में खो गई? प्रशासनिक हलकों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि कई बार जांचें शुरू तो बड़े शोर के साथ होती हैं, लेकिन बाद में उनका पता तक नहीं चलता।

पत्नी के नाम निजी स्कूल और सांसद निधि पर भी सवाल

मामले में नया मोड़ तब आया जब परिवार से जुड़े निजी स्कूल को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुईं, स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि परिवार द्वारा संचालित निजी स्कूल को सांसद निधि से अनुदान मिला,अब जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या निजी स्कूलों को इस प्रकार की सहायता नियमानुसार दी जा सकती है? यदि दी गई,तो किस प्रक्रिया के तहत? किस आधार पर पात्रता तय हुई? और क्या अन्य निजी स्कूलों को भी समान अवसर मिला? यही कारण है कि अब शिक्षा विभाग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

नई कलेक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती

अब जिले में नई प्रशासनिक व्यवस्था बनने के बाद सबसे अधिक निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या वर्षों से चली आ रही इस स्थायी प्रतिनियुक्ति व्यवस्था की समीक्षा होगी,क्या सेवा रिकॉर्ड की जांच होगी? क्या प्रतिनियुक्ति समाप्त होगी? क्या शिकायतों की फाइलें फिर से खुलेंगी? क्या विभागीय जवाबदेही तय होगी? कर्मचारियों का कहना है कि कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील कार्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए,लेकिन दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि वर्षों में मजबूत हो चुके नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं होगा।

सबसे बड़ा सवाल–आखिर सिस्टम चला कौन रहा है?

पूरे मामले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था नियमों से चल रही है या फिर वर्षों से बने प्रभावशाली नेटवर्क से? क्या कमिश्नर सरगुजा इस पूरे मामले में गंभीर संज्ञान लेंगी? क्या प्रतिनियुक्ति व्यवस्था की समीक्षा होगी? क्या विभागीय रिकॉर्ड और पदोन्नति की जांच होगी? क्या शिकायतों और गायब फाइलों का सच सामने आएगा? या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों की धूल में दबकर रह जाएगा? फिलहाल कोरिया कलेक्ट्रेट में चर्चा सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं, बल्कि उस स्थायी सिस्टम की है, जो शायद सरकारी नियमों से ज्यादा मजबूत साबित हो चुका है।

सर्विस बुक आखिर है कहां?

मामले में एक और बड़ा सवाल सर्विस पुस्तिका यानी सर्विस बुक को लेकर खड़ा हो गया है, आखिर संबंधित कर्मचारी की मूल सर्विस बुक कहां है? राजस्व विभाग में? मत्स्य निगम विभाग में? या फिर फाइलों के उसी जंगल में, जहां कई शिकायतें रास्ता भटक चुकी हैं? सूत्र बताते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत कई बार जानकारी मांगी गई, लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, आरोप यह भी है कि जिन टेबलों पर सूचना से संबंधित फाइलें आती थीं, उन्हीं टेबलों पर संबंधित कर्मचारी स्वयं बैठे रहते थे, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यदि किसी कर्मचारी से जुड़े मूल दस्तावेज और सेवा रिकॉर्ड तक स्पष्ट नहीं हैं, तो फिर इतने वर्षों तक उनकी पदस्थापना कैसे बनी रही?

शिकायतें हुईं...लेकिन कार्रवाई फाइलों में ही दफन?

प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा भी वर्षों से बनी हुई है कि संबंधित स्टेनो के खिलाफ कई शिकायतें हुईं, सूत्रों के अनुसार शिकायतें एसीबी तक पहुंचीं, उच्च स्तर तक गईं,लेकिन किसी बड़ी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई,अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर शिकायतों का हुआ क्या? क्या जांच शुरू हुई लेकिन पूरी नहीं हुई? क्या फाइलें आगे बढ़ीं ही नहीं? या फिर सरकारी कार्यालयों की पुरानी परंपरा के अनुसार विचाराधीन होकर किसी अलमारी में आराम कर रही हैं? कर्मचारियों के बीच अब यह व्यंग्य भी सुनाई देता है कि कुछ शिकायतें इतनी संवेदनशील होती हैं कि वे सीधे कार्रवाई तक नहीं पहुंचतीं, पहले धूल की कई परतों से गुजरती हैं।

कलेक्टर बदलते रहे...लेकिन प्रभाव नहीं बदला

सूत्र बताते हैं कि वर्षों में कई कलेक्टर आए और गए, लेकिन संबंधित स्टेनो का प्रभाव लगातार बना रहा, कई कर्मचारियों का आरोप है कि हर नए अधिकारी से करीबी बनाकर उन्होंने खुद को हमेशा सुरक्षित बनाए रखा, धीरे-धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि फाइलों की गति, शिकायतों की दिशा और अधिकारियों तक पहुंचने वाली जानकारी को लेकर भी चर्चाएं होने लगीं, कुछ कर्मचारी तो यहां तक कहते हैं कि कलेक्ट्रेट में कौन-सी फाइल कितनी तेज चलेगी, इसका निर्णय नियमों से पहले व्यवस्था तय करती थी, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन चर्चाएं इतनी व्यापक हैं कि अब प्रशासनिक संतुलन पर भी सवाल उठने लगे हैं।

जिला अध्यक्ष का चुनाव वर्षो से अधर में...विवादित बैठक के बाद समाज में मचा घमासान

खुद का चुनाव नहीं, अब समाज को दे रहे फरमान!

विवादित अध्यक्ष और बहिष्कार का ड्रामा, साहू समाज में मचा घमासान

प्रदेश अध्यक्ष के आदेश ठंडे बस्ते में, जिले में चलता रहा 'स्वयंभू राज'

जब अध्यक्ष ही विवादित,तो बहिष्कार किस आधार पर?

साहू समाज में दो फाड़: कुर्सी बचाने बहिष्कार का हथियार?

समाज से बड़ा कौन? विवादित नेतृत्व पर उठे कानूनी सवाल

अध्यक्ष पद रिक्त,फिर भी जारी बहिष्कार का फरमान!

कुर्सी,समाज और बहिष्कार: कोरिया साहू समाज का अंदरूनी संग्राम

'हम ही अध्यक्ष' की जिद में उलझा समाज, अब फैसलों पर उठे सवाल

खुद प्रदेश अध्यक्ष की नहीं मानी, अब समाज से बहिष्कार का फरमान!

कोरिया साहू समाज में नेतृत्व संकट गहराया, विवादित अध्यक्ष, बंटी हुई समाज व्यवस्था और बहिष्कार प्रस्ताव ने खड़े किए बड़े सवाल

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया, 18 मई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले में साहू समाज इन दिनों गहरे आंतरिक विवाद, नेतृत्व संकट और सामाजिक टकराव के दौर से गुजर रहा है,जिला अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से चली आ रही खींचतान अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है,जहां समाज के भीतर ही समाज की वैधता और फैसलों की संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं।

मामला तब और ज्यादा गरमा गया जब ग्राम स्तर पर आयोजित एक सामाजिक बैठक में कुछ लोगों द्वारा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी सामने आई,इस बैठक के बाद अब पूरे जिले में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर जब स्वयं जिला अध्यक्ष का पद ही विवादित है,चुनाव वर्षों से नहीं हुए हैं और प्रदेश नेतृत्व के आदेशों को

लगातार नजरअंदाज किया गया,तब किसी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार आखिर किसके पास है? यह विवाद अब केवल समाज की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है,बल्कि कानूनी,सामाजिक और संवैधानिक बहस का विषय बनता जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है...

आज पूरे कोरिया जिले में एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, जब स्वयं समाज का जिला अध्यक्ष पद विवादित है,चुनाव नहीं हुए,प्रदेश अध्यक्ष के आदेशों का पालन नहीं हुआ और संगठन दो हिस्सों में बंटा दिखाई दे रहा है,तब किसी सामाजिक बहिष्कार के फैसले को आखिर कौन मानेगा? और उससे भी बड़ा सवाल क्या समाज अब संगठनात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा,या फिर नेतृत्व की यह लड़ाई आने वाले समय में और बड़ा विवाद बन जाएगी?

चुनाव नहीं, फिर भी कुर्सी कायम!

साहू समाज के भीतर पिछले कई महीनों से जिला अध्यक्ष पद को लेकर विवाद बना हुआ है, समाज के कई वरिष्ठ लोगों और युवाओं का आरोप है कि जिला अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं कराए गए, प्रदेश स्तर से कई बार चुनाव कराने के निर्देश दिए गए, बैठकें बुलाई गईं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से मामला टलता गया, समाज के भीतर अब व्यंग्य में यह कहा जाने लगा है कि जिला अध्यक्ष पद एटीकेटी व्यवस्था में चल रहा है, यानी कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद पद पर बने रहने की परंपरा बन गई है, आरोप यह भी है कि वर्तमान विवादित नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों को भी गंभीरता से नहीं लिया, प्रदेश संगठन की ओर से जब चुनाव कराने और नई कार्यकारिणी गठित करने की पहल की गई, तब भी स्थानीय स्तर पर उसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया, यहीं से समाज के भीतर दो धड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे।

अपने आप को मान लिया अध्यक्ष

समाज के कई लोगों का कहना है कि जिला स्तर पर संगठनात्मक स्थिति इतनी अस्पष्ट हो चुकी है कि अब अलग-अलग गुट स्वयं को अधिकृत मानकर कार्य कर रहे हैं, एक पक्ष खुद को वैध नेतृत्व बताता है, जबकि दूसरा पक्ष प्रदेश संगठन के आदेशों और चुनाव प्रक्रिया की मांग कर रहा है, आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग बिना वैधानिक प्रक्रिया के स्वयं को अध्यक्ष घोषित कर बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और समाज के नाम पर फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है कि अब समाज के भीतर यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि यदि संगठनात्मक स्थिति ही स्पष्ट नहीं है, तो किसी सामाजिक दंड या बहिष्कार संबंधी निर्णय की वैधता कैसे तय होगी?

अधिवक्ता मधुसूदन साहू के पत्र ने बढ़ाया विवाद

मामले में नया मोड़ तब आया जब अधिवक्ता मधुसूदन साहू द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर जिला अध्यक्ष पद की वैधता, चुनाव प्रक्रिया और समाज में चल रही गतिविधियों पर सवाल खड़े किए गए, सूत्रों के अनुसार, पत्र में यह उल्लेख किया गया कि जब जिला अध्यक्ष पद पर वैधानिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, तब समाज के नाम पर लिए जा रहे फैसले विवादित माने जाएंगे, पत्र में यह भी सवाल उठाया गया कि आखिर प्रदेश संगठन के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा और चुनाव प्रक्रिया को बार-बार क्यों टाला जा रहा है? बताया जा रहा है कि इसी पत्र के बाद समाज के भीतर हलचल तेज हुई और एक सामाजिक बैठक आयोजित कर कुछ लोगों के खिलाफ बहिष्कार जैसी कार्रवाई पर चर्चा की गई।

ग्राम सरई की बैठक बनी विवाद का केंद्र

17 मई 2026 को ग्राम सरई में आयोजित एक बैठक अब पूरे विवाद का केंद्र बन गई है, बैठक का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया गया, जिसमें कई लोगों के हस्ताक्षर भी मौजूद बताए जा रहे हैं, रजिस्टर में कथित रूप से उल्लेख किया गया कि कुछ लोगों द्वारा सामूहिक विवाह अथवा अंतरजातीय विवाह योजना से जुड़ी गतिविधियों को लेकर समाज नाराज है और ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार जैसी कार्रवाई की जाएगी, यहीं से विवाद और गहरा गया, अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोई भी सामाजिक समूह संविधान और कानून से ऊपर जाकर किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग-थलग करने का निर्णय ले सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल क्या बिना वैध जिला अध्यक्ष और विधिवत अधिकृत कार्यकारिणी के ऐसा प्रस्ताव कानूनी रूप से टिक सकता है?

बिना अध्यक्ष के हस्ताक्षर बहिष्कार मान्य नहीं...

समाज के कई वरिष्ठ लोगों का कहना है कि किसी भी सामाजिक निर्णय की वैधता के लिए अधिकृत अध्यक्ष और विधिवत गठित कार्यकारिणी का होना जरूरी है, यदि जिला अध्यक्ष पद ही विवादित हो, चुनाव न हुए हों और प्रदेश संगठन उस पद को लेकर स्पष्ट स्थिति में न हो, तो किसी बैठक में पारित प्रस्ताव की कानूनी स्थिति स्वतः कमजोर हो जाती है, कई समाजजनों का कहना है कि संबंधित रजिस्टर में वैधानिक अध्यक्ष के अधिकृत हस्ताक्षर तक स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में बहिष्कार संबंधी निर्णय को सामाजिक या कानूनी मान्यता मिलना कठिन माना जा रहा है, कुछ लोगों ने तो यहां तक सवाल उठा दिए कि जब स्वयं समाज का बड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों को नहीं मान रहा, तब आम समाजजन किसी बहिष्कार प्रस्ताव को क्यों और किस आधार पर मानेंगे?

मामला केवल समाज का नहीं, कानून का भी, अंतरजातीय विवाह योजना से जुड़ा है पूरा विवाद-

इस पूरे मामले को गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसका संबंध राज्य सरकार की छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978 (संशोधित 2019) से भी जोड़ा जा रहा है, इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है, योजना के तहत पात्र दंपतियों को ?2.50 लाख से ?3 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि समाज में समानता बढ़े, जातिगत भेदभाव समाप्त हो और सामाजिक समरसता मजबूत हो, ऐसे में यदि किसी दंपति को इस योजना का लाभ लेने पर सामाजिक दबाव, धमकी या बहिष्कार का सामना करना पड़े, तो मामला केवल सामाजिक विवाद नहीं रह जाता, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और कानूनी संरक्षण से जुड़ा विषय बन जाता है।

क्या बहिष्कार का फैसला अपराध की श्रेणी में आ सकता है? कानूनी विशेषज्ञों की नजर में गंभीर मामला

कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी वैवाहिक पसंद,अंतरजातीय विवाह या सरकारी योजना का लाभ लेने के कारण सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई संभव है,यदि किसी बैठक में लोगों को सामाजिक रूप से अलग-थलग करने, आर्थिक या सामाजिक दबाव बनाने अथवा सार्वजनिक अपमानित करने का प्रस्ताव पारित किया गया हो,तो यह मामला संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ सकता है,विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सामाजिक संगठन को संविधान से ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं हैं, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है।

समाज के भीतर बढ़ता असंतोष,युवा वर्ग खुलकर उठा रहा सवाल

इस पूरे विवाद के बाद साहू समाज के भीतर युवा वर्ग में काफी नाराजगी देखी जा रही है,कई युवाओं का कहना है कि समाज को आधुनिक सोच और शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां नेतृत्व की लड़ाई और पद की राजनीति में समाज की छवि खराब हो रही है, कुछ युवाओं ने यह भी कहा कि समाज को संगठित करने के बजाय गुटबाजी और व्यक्तिगत वर्चस्व की राजनीति ने स्थिति को और खराब किया है, समाज के भीतर अब यह मांग भी उठने लगी है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं और वैधानिक जिला अध्यक्ष चुना जाए।

प्रदेश नेतृत्व की चुप्पी पर भी सवाल

समाज के कई लोगों का कहना है कि यदि प्रदेश स्तर से समय रहते सख्त निर्णय लिए जाते और चुनाव प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जाता, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती,अब जब विवाद खुलकर सामने आ चुका है, तब प्रदेश नेतृत्व की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं,लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर प्रदेश संगठन विवादित नेतृत्व पर क्या कार्रवाई करेगा? क्या चुनाव कराए जाएंगे? क्या बहिष्कार प्रस्ताव को वैध माना जाएगा? और क्या समाज के भीतर चल रही समानांतर व्यवस्था पर रोक लगेगी?

प्रशासन भी रखे हुए है नजर

सूत्रों के अनुसार,पूरे घटनाक्रम पर प्रशासनिक स्तर पर भी नजर रखी जा रही है,यदि किसी व्यक्ति या परिवार को सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने,सरकारी योजना का लाभ लेने से रोकने या जातिगत दबाव बनाने की शिकायत मिलती है,तो प्रशासनिक हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता,विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मामला सामाजिक बहिष्कार और अंतरजातीय विवाह जैसी संवेदनशील विषयवस्तु से जुड़ा हुआ है।

प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की बड़ी मांग

हसदो नदी के दोनों तटों पर 500 मीटर क्षेत्र को घोषित किया जाए 'नो-कंस्ट्रक्शन' और प्लांटेशन जोन

-संवाददाता-

सोनहत (कोरिया),18 मई 2026 (घटती-घटना)। विकासखंड सोनहत के ग्राम पोड़ी में आयोजित 'सुशासन तिहार' शिविर इस बार केवल प्रशासनिक समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हसदो नदी के संरक्षण और वनांचल के भविष्य को बचाने की भावुक अपील का मंच भी बना,प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने प्रदेश उपाध्यक्ष राजन पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष अजय गुप्ता और ब्लॉक अध्यक्ष एहसानुल हक के नेतृत्व में कलेक्टर कोरिया के नाम एसडीएम सोनहत को ज्ञापन सौंपकर हसदो नदी के पुनरुद्धार के लिए ग्रीन हसदो कॉरिडोर बनाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि सोनहत क्षेत्र, जिसे कभी कोरिया का शिमला कहा जाता था, आज लगातार बढ़ते

तापमान,घटते जंगल और सूखते जल स्रोतों की मार झेल रहा है, जीवनदायिनी हसदो नदी अपने उद्गम क्षेत्र में ही संकट से जूझ रही है, यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में अमृतधारा और गौर घाट जैसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल केवल इतिहास और किताबों तक सीमित होकर रह जाएंगे, एसोसिएशन ने मांग की है कि मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी संरक्षण मॉडल की तर्ज पर हसदो नदी के उद्गम स्थल से अमृतधारा तक दोनों तटों के 500 मीटर दायरे को नो-कंस्ट्रक्शन जोन और ट्री प्लांटेशन जोन घोषित किया जाए, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर नदी के प्राकृतिक स्वरूप और जलस्तर को संरक्षित किया जाए, इसके अलावा हलफली और बनिया जैसी सहायक जलधाराओं के जलग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम और जल संरक्षण कार्य कराने की मांग भी रखी गई, ज्ञापन में क्षेत्र में चल रही ड्रिलिंग और खनन गतिविधियों का जलस्तर पर पड़ रहे प्रभाव की वैज्ञानिक जांच कराने की भी मांग शामिल है, राजन पाण्डेय ने कहा कि हसदो नदी का संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है,उन्होंने जिला प्रशासन,वन विभाग और स्थानीय पंचायतों की संयुक्त भागीदारी से एक व्यापक हसदो संरक्षण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता बताई, उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि हसदो की पुकार केवल एक नदी का दर्द नहीं,बल्कि पूरे वनांचल की पीड़ा है,अब क्षेत्रवासियों की निगाह प्रशासन पर टिकी है कि 'सुशासन तिहार' के इस मंच से हसदो नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

नरेंद्र मोदी से देश संभल नहीं रहा...अमरजीत भगत

बढ़ती महंगाई,पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस का हमला

जिला कांग्रेस की प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

-संवाददाता-

सूरजपुर,18 मई 2026 (घटती-घटना)। बढ़ती महंगाई,पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को जिला मुख्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की गई, प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला गया।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सूरजपुर जिले के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री देशवासियों से गैस,पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील करते हैं,वहीं दूसरी ओर स्वयं और उनके मंत्री बड़े-बड़े वाहनों के काफिले के साथ चलते दिखाई देते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, अमरजीत भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से सोना नहीं खरीदने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि कांग्रेस शासनकाल की तुलना में आज सोने की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और घरेलू रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है।

महंगाई से किसान और आम जनता परेशान

पूर्व मंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिल पा रहा है,जिससे कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है,वहीं पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है,उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई नियंत्रण में पूरी तरह विफल साबित हो रही है,उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं,जबकि देश की आर्थिक स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है,अमरजीत भगत ने कहा कि वर्तमान हालात यह संकेत दे रहे हैं कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और केंद्र सरकार हालात संभालने में असफल दिखाई दे रही है।

कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र सरकार को घेरा

प्रेसवार्ता में जिला कांग्रेस महामंत्री संजय डोसी, प्रवक्ता गिरजा शंकर मिश्रा,कांग्रेस नेता पंकज तिवारी, वेदप्रकाश मिश्रा,विमलेश दत्त तिवारी,संतोष पावले,शांतू डोसी,शक्ति ठाकुर,परमेश्वर रजवाड़े और विक्की समाद्दार सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे,प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को आम जनता,किसानों और मध्यम वर्ग के लिए नुकसानदायक बताते हुए महंगाई पर नियंत्रण की मांग की।

19 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/18/2026 10:19 PM Page 7

40 सितारों की फौज से क्यों गायब हैं उदय और मजनू भाई?

वेलकम टू द जंगल में 40 सितारों की फौज में फैंस मजनूं और उदय की ओजी जोड़ी को मिस कर रहे हैं। कल्ट फिल्म वेलकम के फैन्स इस फ्रैंचाइजी को उदय भाई और मजनू भाई के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। हालांकि इसकी तीसरी वेलकम टू जंगल जल्द ही रिलीज होने वाली है, कुछ दिन पहले ही इसका टीजर रिलीज हुआ है और अब इसका टाइटल ट्रैक भी रिलीज हो गया है। इस बीच फैंस लगभग 40 सितारों की फौज वाली फिल्म उदय और मजनू भाई की आईकॉनिक जोड़ी को मिस कर रहे हैं। लेकिन नाना पाटेकर ने खुद ही खुलासा कर दिया था कि वे और अनिल कपूर इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं बने।

वेलकम टू द जंगल का हिस्सा क्यों नहीं है उदय और मजनू?

एक इंटरव्यू में, नाना ने बताया था कि उन्होंने आने वाली तीसरी फिल्म, वेलकम टू द जंगल का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। नाना ने 2007 की कल्ट कॉमेडी वेलकम की सफलता का श्रेय डायरेक्टर अनीस बज्मी को दिया। नाना ने तर्क दिया, लेकिन अगर अनिल और मैं इसे साथ में नहीं करते, तो यह पूरा नहीं होता। अगर अनिल और मैं हैं, तभी वेलकम मुमकिन है। अगर आप मुझे हटा दें, तो वह अकेले वेलकम नहीं बना सकते और ठीक इसका उलटा भी।

कहानी नहीं आई पसंद

उन्होंने याद किया कि फिल्म का सीक्वल, वेलकम बैक जिसे अनीस ने ही डायरेक्ट किया था,बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। फिर नाना ने बताया कि उन्होंने और अनिल ने अहमद खान की आने वाली थ्रीक्वल,वेलकम टू द जंगल को क्यों मना कर दिया। नाना ने आगे कहा,उन्होंने हमसे

संपर्क किया था। लेकिन हमने मना कर दिया। कहानी नहीं है, उतना मजा नहीं आया।

अनीस बज्मी की 2007 की ब्लॉकबस्टर फिल्म में अक्षय कुमार,कैटरीना कैफ, परेश रावल, फिरोज ख़ान और मल्लिका शेरावत भी नजर आए थे। 2015 के सीक्वल में अनिल, नाना और परेश ने अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाई, लेकिन मुख्य किरदारों की जगह जॉन अब्राहम और श्रुति हासन को ले लिया गया। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और डिंपल कपाड़िया को भी शामिल किया गया था। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई।

वेलकम टू द जंगल के बारे में...

वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में कई सितारे शामिल हैं। अक्षय कुमार के साथ एक्शन कॉमेडी में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, संजय दत्त, परेश रावल, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, अरशद वारसी, बॉबी देओल जैसे कई सितारे मौजूद हैं।

शाहरुख खान ने रात 2 बजे कुत्ते की कब्र खोदी,बॉडी घर क्यों लाए?

शाहरुख खान सिर्फ अपने सुपरस्टारडम और आइकॉनिक फिल्म करियर के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी इमोशनल और गहरी कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं। बार-बार, एक्टर के बारे में पुराने किस्से ऑनलाइन सामने आते रहते हैं और फैंस को उनकी और भी ज़्यादा तारीफ़ करने पर मजबूर कर देते हैं। और अब,शाहरुख और उनके प्यारे पेट डॉग से जुड़ी एक और अनसुनी कहानी सोशल मीडिया पर दिल जीत रही है। गौरी खान के अंकल की एक वायरल क्लिप ने एक्टर के शुरुआती दिनों की एक इमोशनल याद ताज़ा कर दी है। उस घटना को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने गौरी और शाहरुख को एक चाइनीज़-पेकिनीज़ ब्रीड का डॉग गिफ्ट किया था, जिसे कपल बहुत प्यार करते थे। हालांकि, शाहरुख की एक शूटिंग के दौरान, पेट की दुखद मौत हो गई। एक्टर की गैरमौजूदगी में, घर के स्टाफ ने डॉग को कपड़े में लपेटा और उन्हें बिना बताए समुद्र किनारे दफना दिया। लेकिन शाहरुख के घर लौटने के बाद जो हुआ, उसने अब फैंस को इमोशनल कर दिया है। गौरी के अंकल के मुताबिक, अपने पेट की मौत के बारे में जानकर एक्टर का दिल टूट गया और उन्होंने ज़ोर देकर पूछा कि कुत्ते को कहाँ दफ़नाया गया है। सुबह करीब 2:30 बजे, एसआरके ने स्टाफ़ मेंबर्स को जगाया, खुद बीच पर गए, कब्र खोदी और अपने पेट को घर वापस ले आए। फिर उन्होंने कुत्ते को अपने घर के बैकयार्ड गार्डन में दफ़ना दिया और रात भर रोते हुए जागते रहे। इस इमोशनल कहानी ने एक बार फिर एसआरके के जानवरों के लिए बहुत प्यार और अपने पेट के साथ उनके गहरे इमोशनल रिश्ते को दिखाया है।

80 दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर,46 साल पहले खर्च से 6 गुना ज्यादा की थी कमाई,विदेश में कॉपी हुई फिल्म

80 के दशक में एक फिल्म ने धांसू कमाई से इतिहास रच दिया था। इस फिल्म पर कई बार रीमेक बना। विदेश में भी फिल्म की कॉपी हुई। 80 के दशक में फिरोज खान की एक एक्शन थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म ने दुनियाभर में इतना तगड़ा कलेक्शन किया था कि मेकर्स मालामाल हो गए थे। फिल्म की ताबड़तोड़ सफलता के बाद विदेशी डायरेक्टर ने भी इसका रीमेक बनाया। फिर भारत में भी एक और रीमेक बनी। मगर कोई भी ऑरिजिनल फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई। आज भी यह फिल्म 80ह्य की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है।

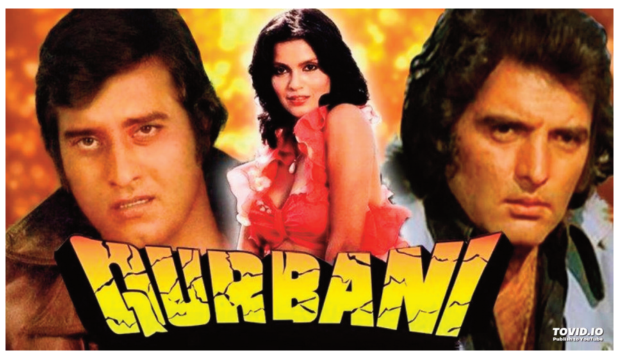

कल्ट बन गई थी फिल्म

इस फिल्म ने खर्च से 6 गुना मुनाफा कमाया था। दुनियाभर में फिल्म की कमाई मुनाफे से भी डबल थी। इस फिल्म में बड़े-बड़े सितारे थे। कहानी और एक्शन भी दमदार था। साथ ही इसके गाने भी कल्ट बन गए।

80 के दौर में क्राइम थ्रिलर का चला जादू

यह फिल्म है 1980 में रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी । फिल्म की कहानी दो दोस्तों की है जिनके बीच एक गलतफहमी जगह ले ली थी। ऊपर से दोनों को एक ही लड़की से इश्क हो जाता है। क्राइम की दुनिया में दोनों की दोस्ती की परीक्षा होती है और क्लाइमैक्स भावुक कर देता है। यह फिल्म सिनेमाघरों को हाउसफुल कर गई थी। मेकर्स मालामाल हो गए थे और सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी। फिल्म में फिरोज खान,जीनत अमान,विनोद मेहरा,अमजद खान और अमरीश पुरी मुख्य भूमिकाओं में थे।

फिल्म का ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, लेकिन इसन 6 गुना ज्यादा यानी 12 करोड़ के पार कारोबार किया था। 80 के दौर में 12 करोड़ कमाना बहुत बड़ी बात थी। यह उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार थी।

श्रीलीला-तिलक वर्मा अफवाहों पर मां ने तोड़ी चुप्पी

टॉलीवुड की यंग सेंसेशन श्रीलीला हाल के दिनों में बैक-टू-बैक फिल्मों और साउथ इंडिया और बॉलीवुड में बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ सबसे बिज़ी एक्ट्रेस में से एक बन गई हैं। एक्ट्रेस अपनी फिल्मों और मेडिकल की पढ़ाई के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन हाल ही में वह यंग इंडियन क्रिकेटर तिलक वर्मा के साथ डेटिंग की अफवाहों के सेंटर में आ गई हैं।

पिछले कुछ दिनों से, सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि श्रीलीला और तिलक वर्मा सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। तिरुमाला में वैकुंठ एकादशी सेलिब्रेशन के दौरान दोनों को अलग-अलग देखे जाने के बाद ये अफवाहें हॉट टॉपिक बन गईं। बाद में, आईपीएल सीज़न के दौरान यह गॉसिप और भी बड़ी हो गई, जब श्रीलीला की मां, डॉ. स्वर्णलता, मुंबई इंडियंस मैच के दौरान व्हीआईपी स्टैंड में कथित तौर पर देखी गईं। फैंस ने भी ऑनलाइन क्लिप और फोटो शेयर करना शुरू कर दिया, हर छोटे इत्तेफाक को अफवाह वाले रिश्ते से जोड़ते हुए। हाल ही में एक वायरल वीडियो जिसमें सूर्यकुमार यादव तिलक वर्मा को यह कहकर चिढ़ा रहे थे कि वह प्यार में हैं ने अटकलों को और हवा दे दी। भले ही सूर्यकुमार ने श्रीलीला का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत कमेंट को एक्ट्रेस से जोड़ दिया।

सूर्या-त्रिशा स्टारर करुप्पु ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़,कंगुवा रिकॉर्ड तोड़ा

करुप्पु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड- सूर्या और त्रिशा कृष्णन स्टारर यह फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ओवरसीज में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। तीन दिनों में, फिल्म ने इंडिया में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और वर्ल्ड वाइड टोटल 100 करोड़ से ज़्यादा कर लिया। इसके साथ ही, सूर्या ने बॉबी देओल के को-स्टारर अपनी पिछली रिलीज़ कंगुवा का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में 28.35 करोड़ कमाए, जिससे ओपनिंग वीकेंड की टोटल कमाई 68 करोड़ हो गई। ओवरसीज में, फिल्म ने रिलीज़ के तीसरे दिन 13 करोड़ कमाए, जिससे ओवरसीज टोटल कमाई 42 करोड़ हो गई। डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों रिकॉर्ड मिलाकर, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 120.75 करोड़ कमाए। करुप्पु ने कंगुवा का लाइफटाइम वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा सूर्या की पिछली स्टारर कंगुवा, जो 2024 में रिलीज़ हुई थी, ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ कमाए थे। करुप्पु ने कंगुवा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और शिवकार्तिकेयन की पराशक्ति को पछाड़कर पहले ही साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फ़िल्म बन गई है। करुप्पु विवाद की वजह भारी एडवांस बुकिंग के बावजूद, फिल्म के फाइनेंसरों और प्रोडक्शन हाउस के बीच एक अनसुलझे फाइनेंशियल विवाद के कारण भारत और विदेशों के कई थिएटरों को स्क्रीनिंग रोकनी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, देरी प्रोडक्शन हाउस पर 50 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज़ से जुड़े फाइनेंशियल रुकावट की वजह से हुई, जिसके कारण थिएटर मालिकों को बुकिंग रोकनी पड़ी और प्रीमियर कैंसिल करने पड़े।

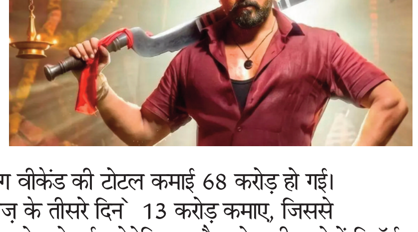

खेल समाचार

भारतीय मूल के गोल्फर एरॉन राय ने अपना पहला पीजीए चैंपियनशिप खिताब जीता

पेंसिल्वेनिया,18 मई 2026। भारतीय मूल के इंग्लिश गोल्फर एरॉन राय ने पीजीए चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। एरोनिमिंक गोल्फ क्लब में शानदार प्रदर्शन करते हुए एरॉन राय साल 1919 के बाद पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले पहले अंग्रेज गोल्फर बने। उनसे पहले जिम बार्न्स यह खिताब जीतने वाले इंग्लिश खिलाड़ी थे। एरोनिमिंक में राय की जीत ने अब उन्हें गोल्फ के सबसे नए मेजर चैंपियंस की लिस्ट में शामिल कर दिया है। यह इस सीजन के सबसे यादगार फाइनल-राउंड प्रदर्शनों में से एक है। इंग्लिश गोल्फर ने रविवार के आखिरी राउंड की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ की थी, लेकिन 17वें होल (पार-3) पर उनकी शानदार बर्डी पुट ने ही टूर्नामेंट का नतीजा तय कर दिया था। एक बड़े खिताब का दबाव झेलते हुए, उन्हें 68 फुट की मुश्किल पुट लगानी थी। राय ने गेंद को होल में डाला, जिसके साथ अपने पीछे चल रहे खिलाड़ियों से तीन शॉट आगे निकल गए। इस पल ने वॉल्वरहैम्प्टन में जन्मे गोल्फर को 18वें होल की ओर बढ़ते समय काफी राहत दी, जहां एक शांत और संयमित पार फिनिश ने उन्हें चैंपियनशिप और प्रतिष्ठित वानामेकर ट्रॉफी दोनों दिला दीं। राय ने यह सप्ताह नाइन-अंडर-पार पर खत्म किया था। वह दूसरे स्थान पर बराबरी पर रहे खिलाड़ियों के समूह से तीन शॉट आगे रहे। तीसरे राउंड के बाद क्लबहाउस में सबसे आगे चल रहे एलेक्स स्मैली ने आखिरी राउंड में इवन-पार स्कोर किया और सिक्स-अंडर पर समाप्त किया, उनके साथ जॉन रहम भी रहे ।

अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान आज

बुमराह को आराम मिल सकता है,रोहित की फिटनेस पर सस्पेंस,पडिक्कल-अकीब नबी पर नजरें...

मुंबई,18 मई 2026। अफगानिस्तान अगले महीने भारतीय दौरे पर आ रही है। उसे यहां 6 जून से एक टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान मंगलवार को होगा। यह दावा पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। इसके अनुसार गुवाहाटी में होने वाली सिलेक्शन कमेटी की बैठक में जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा सकता है। साथ ही रोहित शर्मा की फिटनेस पर भी चर्चा होगी। देवदत्त पडिक्कल,आकिब नबी और प्रिंस यादव पर भी नजरें रहेंगी। सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक बुमराह को टेस्ट और वनडे में साथ खिलाने की संभावना कम है। उन्हें वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है। ताकि उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए फिट रखा जा सके। उनके मामले में टीम मैनेजमेंट कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज भारत के पेस अटैक को लीड कर सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का चयन भी तय माना जा रहा है। पीठ की समस्या से जूझ रहे हार्दिक पंड्या की उपलब्धता अब भी स्पष्ट नहीं है।

रोहित पर फैसला बाकी, विराट खेलेंगे वनडे

रोहित शर्मा आईपीएल में मांसपेशियों की चोट से जूझते रहे हैं। वे आईपीएल में मुंबई के कई मैचों से बाहर रहे। ऐसे में सिलेक्टर्स उन्हें वनडे टीम में तभी शामिल करेंगे, जब वे पूरी तरह फिट होंगे। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली के सभी वनडे खेलने की संभावना है।

नंबर-3 के लिए पडिक्कल पर दांव चेतेश्वर पुजारा के बाहर होने के बाद भारत को टेस्ट में नंबर-3 पर स्थायी बल्लेबाज नहीं मिला है। साई सुदर्शन को मौके मिले, लेकिन वे प्रभाव नहीं छोड़ सके। अब देवदत्त पडिक्कल को लंबी अवधि के विकल्प के तौर पर तैयार करने की योजना है।

आकिब नबी और प्रिंस यादव पर नजरें

रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर के लिए 60 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी को टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है। वहीं, आईपीएल में तेज गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले प्रिंस यादव वनडे टीम की रेस में हैं।

पीबीकेएस पर जीत के साथ आरसीबी तालिका में शीर्ष पर

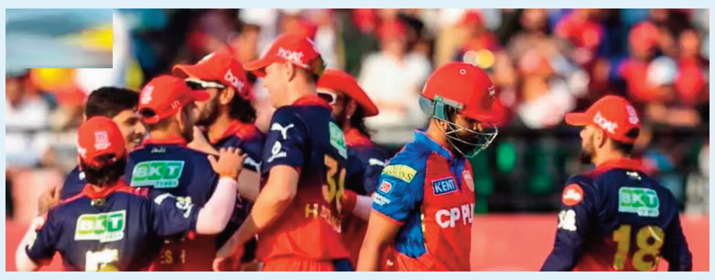

धर्मशाला,18 मई 2026। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यहां पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर अपना धैर्य बनाए रखा और आरसीबी प्लेऑफ़ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों में शानदार 73 रन बनाए और आरसीबी को चार विकेट पर 222 रन तक पहुंचाया। विराट कोहली (37 गेंदों में 58 रन), देवदत्त पडिक्कल (25 गेंदों में 45 रन) और टिम डेविड (12 गेंदों में 28 रन) ने आरसीबी के लिए दूसरे अहम योगदान दिए, जब उन्हें पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया। जवाब में, शशांक सिंह के 27 गेंदों में 56 रन की ज़बरदस्त पारी की बदौलत पीबीकेएस आठ विकेट पर 199 रन पर रुक गई, होम टीम को सीज़न की शानदार शुरुआत के बाद लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा।

आरआर पर जीत के साथ डीसी ने अपनी प्लेऑफ स्थिति मजबूत की...

नई दिल्ली,18 मई 2026। मिचेल स्टार्क ने यहां राजस्थान रॉयल्स की बढ़त को रोकने के लिए चार विकेट लेकर गेम बदल दिया,जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने पांच विकेट से अहम जीत हासिल की और आईपीएल प्ले-ऑफ में अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं। स्टार्क के शानदार 4/40 की वजह से राजस्थान की टीम 14 ओवर में दो विकेट पर 160 रन बनाकर बुरी तरह हार गई, और मेहमान टीम आखिर में सिर्फ 33 रन ही बना पाई और छह विकेट खोकर आठ विकेट पर 193 रन बना सकी। इसके बाद दिल्ली ने केएल राहुल (42 रन पर 56 रन) और अभिषेक पोरेल (31 रन पर 51 रन) की शानदार ओपनिंग साझेदारी से सिर्फ 10.1 ओवर में 105 रन की शानदार ओपनिंग साझेदारी से टीम को जीत दिलाई। पोरेल ने शुरू से ही सात चौके और एक छक्का लगाया, जबकि राहुल ने दासुन शनाका की गेंद पर आउट होने से पहले अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। साहिल पारख ने तेज़ी से 9 रन बनाए, जिसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंदों पर दो चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 34 रन बनाकर मैच को खत्म किया।

CMYK

किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे शर्त पर अनिल टुटेजा को मिली जमानत

रायपुर, 18 मई 2026। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि टुटेजा को 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि इस मामले के अन्य सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने टिप्पणी की कि टुटेजा के खिलाफ करीब 85 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है और ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर जरूर हैं, लेकिन उनकी सच्चाई ट्रायल के दौरान ही तय होगा। आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, अनिल टुटेजा जमानत पर रिहा होने के बाद राज्य से बाहर रहेंगे और किसी भी सेवारत सरकारी अधिकारी से संपर्क नहीं करेंगे। इसके अलावा, वह गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। ईडी के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। ईडी का अनुमान है कि इस अवैध धंधे से करीब तीन हजार करोड़ रुपए की गैरकानूनी कमाई हुई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। ईडी के अनुसार, इस घोटाले की जांच में एक संगठित सिंडिकेट का पता चला, जिसमें नौकरशाह, राजनीतिक नेता और निजी कारोबारी शामिल थे।

रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक से लूट, आरोपी अरेस्ट

मॉर्निंग वॉक के समय मोबाइल छीनकर भागा था, भूपेश बोले...'सुशासन' पर तमाचा

रायपुर, 18 मई 2026। रायपुर में बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक मॉर्निंग वॉक के दौरान मोबाइल लूट का शिकार हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी ब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सोमवार सुबह जब कौशिक पैदल चल रहे थे, तभी झपटमार उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि वे संभल भी नहीं सके। हालांकि, पुलिस ने आरोपी मणिकांत ध्रुव (19) को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पेशे से रैपिडो ड्राइवर है। वह मूल रूप से बलौदाबाजार जिले का रहने वाला है और वर्तमान में रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र स्थित राजीव नगर में रह रहा है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि 'आप डायल 112 को झंडी दिखाते रहिए, उधर धरम लाल कौशिक जी का मोबाइल छीनकर चोर 9-2-11 हो गए। उन्होंने आगे लिखा-सोचिए जरा, जब देश के गृहमंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में हैं, उस समय 'मॉर्निंग वॉक' के दौरान ऐसी घटना कथित 'सुशासन' पर तमाचा है।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में अत्याधुनिक 'नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा' और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का किया शुभारंभ

400 अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन एवं 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को दिखाई हरी झंडी

रायपुर, 18 मई 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने माना पुलिस परेड ग्राउंड, रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस की अत्याधुनिक 'नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा' तथा मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह एवं की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 400 अत्याधुनिक डायल-112 वाहनों तथा 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 'एक्के नंबर, सब्बो बर' थीम पर आधारित यह आधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को एक ही नंबर पर त्वरित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके तहत शुरू किए गए 400 अत्याधुनिक वाहनों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन तकनीकों की मदद से घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और त्वरित संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह सेवा 24×7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी तथा स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और SOS-112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। 'Science on Wheels - Towards Faster Justice' थीम पर आधारित 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदेश में अपराध अनुसंधान को नई दिशा देंगी। '32 वैन - 32 जिले - एक संकल्पः सटीक जांच, त्वरित न्याय' के उद्देश्य के साथ शुरू की गई यह पहल घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी। लगभग 65 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत वाली इन अत्याधुनिक वैन में घटनास्थल संरक्षण किट, साक्ष्य संग्रहण एवं सीलिंग उपकरण, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नार्कोटिक्स परीक्षण किट, डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट, उच्च गुणवत्ता फोटोग्राफी व्यवस्था, बुलेट होल स्क्रीनिंग एवं बैलिस्टिक जांच किट तथा गनशॉट रेजिड्यू परीक्षण किट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब तक अपराध स्थल से साक्ष्य प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में समय लगता था, जिससे साक्ष्यों के दूषित होने की संभावना बनी रहती थी तथा रिपोर्ट आने में भी विलंब होता था। नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन के माध्यम से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक जांच, साक्ष्य संरक्षण, परीक्षण और डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। इससे जांच की गुणवत्ता और गति दोनों में महत्वपूर्ण सुधार होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य वैज्ञानिक जांच को जन-जन तक पहुंचाना, साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली को मजबूत करना, अपराध नियंत्रण में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना तथा समयबद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करना है। आधुनिक डायल-112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन के संचालन से प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा, अपराध अनुसंधान को नई गति मिलेगी तथा आम नागरिकों का कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि,

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले एक हजार से अधिक अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की धरती पर शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने में हमारे जवानों का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करने, विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और माओवाद के समूल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

गुंडाधुर की धरती बनेगी तीर्थस्थल 50 सालों में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई 4-5 साल में करेंगे : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद खात्मे के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों का 50 सालों में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम 4-5 सालों में करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब तक बस्तर विकसित नहीं होगा, तब तक हमारा संकल्प अधूरा रहेगा। इससे पहले नेतानार में शाह ने कहा कि, आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले 6 महीनों के काम के बाद अब यह पूरा क्षेत्र आदिवासियों से भरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी धरा से अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने का काम अमर शहीद गुंडाधुर ने किया था। शाह ने कहा कि एक दौर वह भी था जब यहां एक साथ 6 पुलिसवालों की हत्या कर दी जाती थी, स्कूल उजाड़ दिए जाते थे और गरीबों का राशन तक छीन लिया जाता था। नक्सलियों का खौफ ऐसा था कि वे मासूम बच्चों को उनके बचपन में ही जबरन उठा ले जाते थे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि अब सरकार ने कड़े कदम उठाकर बस्तर से इस गनतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अब इस ऐतिहासिक धरती को एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया जा रहा है। यहां के आदिवासी बच्चों को अब वे तमाम आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जो पहले केवल बड़े शहरों में ही मिलती थीं। अब हर गरीब परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जा रहा है, उनके राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। नेतानार के बाद अमित शाह जगदलपुर के आसना में स्थित बादल अकादमी पहुंचे। यहां बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसबी और एनटीआरओ के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी सुंदरराज पी का भी सम्मान किया गया। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जवानों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की। उन्होंने बसवाराजू समेत 38 नक्सलियों के एनकाउंटर के बारे में बताया। इस दौरान नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों ने भी अपना दर्द बयां किया। जगरगुंडा की रहने वाली जानकी कश्यप ने बताया कि उनकी आंखों के सामने नक्सलियों ने उनके देवर समेत 7-8 लोगों की हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवारों ने कहा कि पहले गांव जाना मुश्किल था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और सड़कों के निर्माण से हालात बदले हैं। शहीद जवान की बहन पिंकी सेठिया ने कहा कि, अब बस्तर के जंगल में ड्यूटी कर रहे जवानों के परिवार वालों को डर नहीं रहेगा कि हमारे बेटे जंगलों में ड्यूटी कर रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स, नमनाकला, संत हरकेवल विद्यापीठ के पास, अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050, डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001, 98265-32611, Email:ghatatighatana11@ gmail.com, Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)